सिटी चीफ

वर्ष-15, अंक-144
पृष्ठ-8 मूल्य 2 रूपया

CITYCHIEFSENDMENEWS@GMAIL.COM

इंदौर, गुरुवार 29 अगस्त 2024

सम्पूर्ण भारत मे चर्चित हिन्दी अखबार

आज का विचार

जो लोग गिरने से डरते हैं वह कभी भी जीवन में उड़ान नहीं भर सकते..

कोलकाता कांड में फंसे पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को आईएमए ने किया सस्पेंड

कोलकाता। कोलकाता के जिस कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर की बलात्कार के बाद हत्या हुई थी, उसके पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) ने सस्पेंड कर दिया है। यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब सीबीआई ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष का नाम उनके कार्यकाल के दौरान संस्थान में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच के संबंध में दर्ज किया है। एजेंसी ने आईपीसी की धारा 120 बी (आपराधिक साजिश) धारा 420 (धोखाधड़ी) के साथ पठित और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 में संशोधित) की धारा सात लगाई है, जो एक लोक सेवक द्वारा अवैध रूप से रिश्वत स्वीकार करने से संबंधित है। कोलकाता के सरकारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में नौ अगस्त को महिला ट्रेनी डॉक्टर का शव मिला था, जिस पर गंभीर चोटों के निशान थे। इस घटना के संबंध में सीबीआई जांच कर रही है। इस घटना के खिलाफ देश भर में व्यापक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्देश पर सीबीआई ने हत्या और कथित वित्तीय अनियमितताओं के मामले दर्ज किए। इससे पहले डॉ. संदीप घोष का सोमवार को लाई डिटेक्टर टेस्ट भी हुआ। उन पर इस मामले में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया गया है। बुधवार शाम जारी एक संक्षिप्त बयान में आईएमए ने कहा, मारे गए डॉक्टर के माता-पिता ने... स्थिति से निपटने में आपके खिलाफ अपनी शिकायतें दर्ज कराई हैं, साथ ही इस मुद्दे को उचित तरीके से संभालने में सहानुभूति और संवेदनशीलता की कमी के बारे में भी उन्होंने बताया है।

पूजा खेडकर ने अपनी अयोग्ता को दिल्ली हाईकोर्ट में दी चुनौती, पेश किया जवाब

नई दिल्ली। ट्रेनी आईएएस अफसर पूजा खेडकर पर अपने पद का दुरुपयोग का आरोप लगने के बाद उनका पद उनसे छीन लिया गया था। अब पूजा ने अपनी अयोग्ता को चुनौती दी है। उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में अपना जवाब दाखिल करते हुए कहा है कि संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) के पास उनके खिलाफ कार्रवाई करने का कोई अधिकार नहीं है। खेडकर ने उल्लेख किया कि अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1954 और प्रशिक्षु नियमों के तहत कार्रवाई केवल डीओपीटी (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) ही कर सकता है, जो सीएसई 2022 नियमों के नियम 19 के अनुसार है। 31 जुलाई को, यूपीएससी ने पूजा खेडकर की अस्थायी उम्मीदवारी रद्द कर दी थी और उन्हें भविष्य की किसी भी परीक्षा या चयन में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया था। यह निर्णय तब लिया गया जब खेडकर को अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने और सीएसई (सिविल सेवा परीक्षा) 2022 नियमों के प्रावधानों के विपरीत कार्य करने का दोषी पाया गया था। यह पया गया कि उन्होंने अपनी पहचान को लेकर झूठी जानकारी दी थी। यूपीएससी ने खेडकर के खिलाफ धोखा, धोखाधड़ी और जालसाजी के लिए भी एक आपराधिक मामला शुरू किया था। इसके बाद, खेडकर ने यूपीएससी के अपने अस्थायी उम्मीदवारी रद्द करने के निर्णय को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया है। अदालत के समक्ष अपने जवाब में, खेडकर ने दावा किया कि उन्होंने यूपीएससी के सामने अपना नाम हेरफेर या गलत तरीके से पेश नहीं किया। उनके जवाब में लिखा है कि आवेदक का पहला नाम और उपनाम 2012 से 2022 तक सभी डीएएफ में लगातार रिफ्लेक्ट होने के कारण कोई बदलाव नहीं हुआ है।

राजविंदर सिंह भट्टी सीआईएसएफ और दलीप सिंह चौधरी बीएसएफ के नए बॉस

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने राजविंदर सिंह भट्टी को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) का महानिदेशक नियुक्त किया है। भट्टी 1990 के बैच के भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के अधिकारी हैं। सेवानिवृत्त होने से पहले 30 सितंबर 2025 तक वह इस पद पर रहेंगे। वहीं, दलीप सिंह चौधरी को सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। चौधरी 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और वर्तमान में एसएसबी के निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। वे सेवानिवृत्त होने से पहले 30 नवंबर 2025 तक इस पद पर रहेंगे। वहीं, बिहार के पुलिस महानिदेशक आर एस भट्टी सीआईएसएफ के महानिदेशक बनाए गए

ग्वालियर में रीजनल इंडस्ट्रीयल कॉन्क्लेवः सीएम मोहन यादव बोले- कहने को रीजनल कॉन्क्लेव...लेकिन यह राज्य स्तरीय कॉन्क्लेव

मप्र में एक साथ 47 नई औद्योगिक इकाइयों की शुरुआत

ग्वालियर। मध्यप्रदेश के ग्वालियर में बुधवार को रीजनल इंडस्ट्रीयल कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। इसमें करोड़ों का निवेश आया तो वहीं पांच जिलों में 47 इकाइयों का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 1586 करोड़ रुपए की लागत से प्रदेश में 47 नई औद्योगिक इकाइयों का सिंगल क्लिक से लोकार्पण और भूमिपूजन किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव एवं अन्य अतिथियों ने इस वर्ष की तृतीय रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का दीप प्रज्जवलन कर शुभारंभ किया। यह कॉन्क्लेव विरासत, इतिहास और उद्योग की थीम पर केंद्रित रहा। मंच पर 5 औद्योगिक इकाइयों को भूमि आवंटन पत्र भी प्रदान किए गए। इसके साथ ही ग्वालियर-चंबल जिले के 8 जिला स्तरीय इंडस्ट्री फेसिलिटेशन सेंटर का शुभारंभ किया गया। ये केंद्र ग्वालियर, मुरैना, भिंड, श्योपुर, शिवपुरी, दतिया, गुना और अशोकनगर में प्रारंभ किए गए हैं। कॉन्क्लेव में मेक्सिको, जाम्बिया के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि ग्वालियर में निजी क्षेत्र में बड़ा चिकित्सालय खोला जाएगा। प्रारंभ में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कृषि विश्वविद्यालय परिसर में राजमाता विजयाराजे सिंधिया की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र के उद्योग विकास की संभावनाओं पर केंद्रित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। सीएम ने कहा कि रीजनल कॉन्क्लेव कहने को रीजनल है, लेकिन यह कॉन्क्लेव राज्य स्तरीय है। इन इकाइयों के प्रारंभ होने से स्पंदन पूरे प्रदेश में होना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुकूलता से उद्यमशीलता का विकास संभव है। ग्वालियर ऋषियों और संगीत साधकों की भूमि रही है। उद्योग और निवेश की दृष्टि से ग्वालियर प्रमुख केंद्र रहा है।

रुग्ण औद्योगिक इकाइयों की समस्याएं हल होंगी

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में हुकुमचंद मिल, इंदौर के श्रमिकों को राशि दिलवाने का कार्य किया गया। यह कार्य अनेक वर्ष से लंबित था। सरकार का यही कर्तव्य होना चाहिए। रुग्ण औद्योगिक इकाइयों की समस्याएं भी हल होना चाहिए। अब ऐसे अन्य मामलों के लिए जरूरी निर्णय दिए जाएंगे। जेसी मिल ग्वालियर की समस्या भी हुकुमचंद मिल की तर्ज पर हल की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इस अवसर पर चिकित्सा और हेल्थ सेक्टर में ग्वालियर में एक निजी क्षेत्र का अस्पताल प्रारंभ करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि सीतापुर में पुलिस चौकी और औद्योगिक क्षेत्र में फायर स्टेशन भी प्रारंभ किए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि कॉन्क्लेव के आयोजन के पीछे यह भाव भी है कि उद्योगपति प्रदेश की विशेषताओं को आकार स्वयं देखें और मध्यप्रदेश में उद्योग स्थापना का निर्णय लें।

छह माह में 1.84 हजार करोड़ का निवेश

केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि ग्वालियर में उद्योग की अलख जगाने का कार्य मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने किया है। इस अंचल के प्रत्येक नागरिक के दिल में उन्होंने स्थान बना लिया है। ग्वालियर अंचल में अधोसंरचना और निवेश की शुरुआत वर्षों पहले की गई। वर्तमान में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश की क्षमताओं के अनुकूल प्रदेश को राष्ट्र पटल पर लाने का कार्य किया है। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की पहल करने वाले प्रथम मुख्यमंत्री हैं डॉ मोहन यादव। सिंधिया ने कहा कि प्रदेश में 6 माह की अवधि में एक लाख 84 हजार करोड़ का निवेश आना सामान्य बात नहीं है। निश्चित ही ग्वालियर चंबल क्षेत्र की तस्वीर नए-नए उद्योगों के आने से बदल जाएगी। सिंधिया ने विभिन्न सेक्टर में उद्योगों के विकास की संभावना पर भी प्रकाश डाला।

प्रदेश में 121 बैठकें कर चुके मुख्यमंत्री

प्रमुख सचिव औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग राघवेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि प्रदेश में 121 बैठकें मुख्यमंत्री डॉ. यादव द्वारा की गई हैं। आगामी 7-8 फरवरी 2025 को भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तैयारी की जा रही है। प्रदेश में निवेश आ रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पिछले दिनों में विभिन्न औद्योगिक इकाइयों के 51 वर्चुअल शुभारंभ किए हैं। इससे लगभग 8300 व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजन होगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जबलपुर, ग्वालियर, चंबल के उद्योगपतियों से चर्चा की है। प्रमुख सचिव सिंह ने उद्योग हितैषी नीतियों संशोधित श्रम नीतियों और ग्वालियर, चंबल संभागों में उद्योगों की प्रगति की संभावनाओं की विस्तृत से जानकारी दी। शुभारंभ सत्र में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य काश्यप, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण, उद्यानिकी मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा, संस्कृति राज्य मंत्री धर्मेंद्र लोधी, सांसद संध्या राय, सांसद भारत सिंह कुशवाह, सांसद शिवमंगल सिंह तोमर, ग्रामोद्योग राज्य मंत्री दिलीप जायसवाल, किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री एदल सिंह कंषाना, जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह मंच पर उपस्थित थे।

आईटी क्षेत्र में 43 प्रतिशत रही प्रगति

प्रमुख सचिव पर्यटन शिवशेखर शुक्ला ने पर्यटन क्षेत्र में विकास की संभावनाओं पर विस्तृत प्रजेंटेशन दिया। प्रमुख सचिव खनिज संजय शुक्ला ने कोयला, लाइम स्टोन, कॉपर एवं अन्य खनिजों के क्षेत्र में प्रदेश की स्थिति की जानकारी दी। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के प्रमुख सचिव संजय दुबे ने अपने प्रजेंटेशन में बताया कि मध्यप्रदेश की प्रगति गत दशक में 11 प्रतिशत रही जबकि आईटी क्षेत्र में प्रगति 43 प्रतिशत रही।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का चिंताजनक खुलासा

देश में जनसंख्या वृद्धि से ज्यादा है छात्र आत्महत्या की दर

नई दिल्ली। भारत में छात्रों की आत्महत्या की घटनाएं बढ़ रही हैं, जोकि एक चिंता का विषय है। इस संबंध में एक नई रिपोर्ट ने इस विषय पर एक और चिंताजनक खुलासा किया है। रिपोर्ट के अनुसार, भारत में छात्रों की आत्महत्या करने की दर, जनसंख्या वृद्धि दर से भी अधिक है। यही नहीं, यह दर कुल आत्महत्या की दर से भी अधिक हो गई है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों के आधार पर, 'छात्र आत्महत्या- भारत में महामारी' रिपोर्ट बुधवार को वार्षिक आईसी 3 सम्मेलन और एक्सपो 2024 में लॉन्च की गई। रिपोर्ट में बताया गया है कि जहां कुल आत्महत्या की संख्या में सालाना 2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, वहीं छात्र आत्महत्या के मामलों में 4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि छात्र आत्महत्या के मामलों की कम रिपोर्टिंग की संभावना है। आईसी 3 संस्थान द्वारा संकलित रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले दो दशकों में, छात्रों की आत्महत्या की दर 4 प्रतिशत की खतरनाक वार्षिक दर से बढ़ी है, जो राष्ट्रीय औसत से दोगुनी है। 2022 में, कुल छात्र आत्महत्याओं में पुरुष छात्रों की संख्या 53 प्रतिशत थी। 2021 और 2022 के बीच, पुरुष छात्रों की आत्महत्या में 6 प्रतिशत की कमी आई, जबकि महिला छात्रों की आत्महत्या में 7 प्रतिशत की वृद्धि हुई। रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले दशक में 0-24 वर्ष की आयु के बच्चों की जनसंख्या 582 मिलियन से घटकर 581 मिलियन हो गई, जबकि छात्र आत्महत्याओं की संख्या 6,654 से बढ़कर 13,044 हो गई।

मध्यप्रदेश सहित तीन राज्यों में सबसे ज्याद छात्र आत्महत्या रिपोर्ट के अनुसार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश वो राज्य हैं, जहां छात्र सबसे ज्यादा आत्महत्या करते हैं। यहां जितने छात्र आत्महत्या करते हैं वह देश में होने वाली कुल आत्महत्याओं का एक तिहाई हिस्सा है। दक्षिणी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सामूहिक रूप से इन मामलों में 29 प्रतिशत का योगदान है, जबकि राजस्थान 10वें स्थान पर है।

लिंग वार हुई इतनी बढ़ोतरी रिपोर्ट में छात्र आत्महत्याओं में चिंताजनक वृद्धि देखी गई। पिछले दशक में पुरुष आत्महत्याओं में 50 प्रतिशत और महिला आत्महत्याओं में 61 प्रतिशत की वृद्धि हुई। पिछले पांच वर्षों में दोनों लिंगों में औसतन 5 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हुई है।

अधिक हो सकती है वास्तविक संख्या एनसीआरबी द्वारा संकलित डेटा पुलिस द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी रिपोर्ट (एफआईआर) पर आधारित है। हालांकि, यह स्वीकार करना महत्वपूर्ण है कि छात्रों की आत्महत्या की वास्तविक संख्या संभवतः कम रिपोर्ट की गई है। इस कम रिपोर्टिंग के लिए कई कारक जिम्मेदार हो सकते हैं, जिसमें आत्महत्या से जुड़ा सामाजिक कलंक और भारतीय दंड संहिता की धारा 309 के तहत आत्महत्या के प्रयास और सहायता प्राप्त आत्महत्या का अपराधीकरण शामिल है। इसके अलावा, एक मजबूत डेटा संग्रह प्रणाली न होने के कारण भी इस डेटा में कई विसंगतियां हैं। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां रिपोर्टिंग शहरी क्षेत्रों की तुलना में कम है। आईसी 3 संस्थान एक स्वयंसेवी-आधारित संगठन है जो अपने प्रशासकों, शिक्षकों और परामर्शदाताओं के लिए मार्गदर्शन और प्रशिक्षण संसाधनों के माध्यम से दुनिया भर के हाई स्कूलों को सहायता प्रदान करता है, ताकि मजबूत करियर और कॉलेज परामर्श विभाग स्थापित करने और बनाए रखने में मदद मिल सके।

राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा

देश में बनेंगे 12 औद्योगिक स्मार्ट शहर, 10 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को देशभर में 12 औद्योगिक स्मार्ट शहर स्थापित करने की मंजूरी दी है। इससे लगभग 10 लाख लोगों को रोजगार मिल सकेगा। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में बताया कि केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 12 औद्योगिक स्मार्ट शहरों को मंजूरी दी है। इससे घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा मिल सकेगा। इस योजना पर 28,602 करोड़ रुपए का निवेश होगा।

मलयालम फिल्म उद्योग पर 10-15 पुरुष निर्माता निर्देशक और अभिनेताओं का नियंत्रण

यौन उत्पीड़न के आरोपों से हिली मलयालम फिल्म इंडस्ट्री...17 केस दर्ज

तिरुवनंतपुरम। यौन उत्पीड़न के आरोपों की बाढ़ से मलयालम फिल्म इंडस्ट्री मॉलीवुड में भूचाल आ गया है। यौन उत्पीड़न के मामलों में अब तक 17 मामले दर्ज किए गए हैं। आरोपों के बीच मलयालम मूवी आर्टिस्ट की एसोसिएशन एएमएमए को भी भंग कर दिया गया है। पुलिस आरोपों को लेकर मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के कई फिल्मी सितारों और फिल्म निर्माताओं से पूछताछ कर सकती है। यौन उत्पीड़न के आरोपों की कड़ी में नया आरोप फिल्म अभिनेत्री सोनिया मल्हार का है। मल्हार का आरोप है कि साल 2013 में एक फिल्म के सेट पर अभिनेता उनके साथ छेड़छाड़ की थी। अभिनेत्री ने केरल सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल के सामने अपनी शिकायत दर्ज कराई है।

केरल सरकार ने इस विशेष जांच दल बनाया मॉलीवुड में यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच के लिए केरल सरकार ने इस विशेष जांच दल का गठन किया है। सोनिया मल्हार से पहले फिल्म अभिनेत्री मीनू मुनीर ने भी यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। मीनू मुनीर का दावा है कि अब उन्हें धमकी भरे संदेश मिल रहे हैं। मीनू ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है। विशेष जांच दल जल्द ही मीनू मुनीर के बयान दर्ज कर सकती है।

फिल्म अभिनेता सिद्दीकी के खिलाफ मामला दर्ज मलयालम फिल्म अभिनेता सिद्दीकी पर भी यौन शोषण का आरोप लगा है। एक फिल्म अभिनेत्री ने सिद्दीकी पर साल 2016 में यौन शोषण करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने इस मामले में आईपीसी की धारा 376 और 506 के तहत केस दर्ज किया है। किसी हाई प्रोफाइल फिल्मी सितारे के खिलाफ यह दूसरी एफआईआर है। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के कई अभिनेताओं, निर्देशकों और फिल्म निमार्ताओं के खिलाफ भी यौन शोषण के आरोप लगे हैं।

रिपोर्ट से आया भूचाल मलयालम फिल्म उद्योग के कुछ शीर्ष लोगों के खिलाफ आरोपों की बाढ़ पिछले सप्ताह न्यायमूर्ति हेमा समिति की रिपोर्ट के सार्वजनिक होने के बाद शुरू हुई है। 235 पन्नों की रिपोर्ट में कहा गया है कि मलयालम फिल्म उद्योग पर 10-15 पुरुष निर्माता, निर्देशक और अभिनेताओं का नियंत्रण है। तीन सदस्यीय न्यायमूर्ति हेमा समिति का गठन राज्य सरकार ने साल 2017 में किया था और इसने 2019 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। रिपोर्ट को अब तक सार्वजनिक नहीं किया गया था क्योंकि इसे जारी करने पर कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था।

सिटी चीफ
सम्पूर्ण भारत मे चर्चित हिन्दी अखबार
Fastest Growing Media Network
अवश्यकता है
इंदौर भोपाल जिले के सभी तहसीलो में दैनिक अख़बार और डिजिटल रिपोर्टर की।
डिजिटल और प्रिंट के लिये मार्केटिंग टीम (मेल/फीमेल) एवं हेल्परो की अवश्यकता हैं
डिजिटल मीडिया का क्रान्तिकारी कदम
डिजिटल भारत में खबरों के लिए देखे सिटी चीफ न्यूज़
रिपोर्टर बनने के लिए सम्पर्क करे
9755996590

सिंगल कॉलम

देवी अहिल्याबाई की पालकी यात्रा को लेकर हुई बैठक, सीएम होंगे शामिल

इंदौर। प्रतिवषार्नुसार निकलने वाली देवी अहिल्याबाई की पालकी यात्रा इंदौर का गौरव प्रसंग है। इस वर्ष भी वह आन-बान और शान से निकले, इसका प्रयत्न हम सभी कार्यकताओं को करना चाहिए। यह बात पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने इस वर्ष 1 सितंबर को देवी अहिल्याबाई की 229वीं पुण्यतिथि पर निकलने वाली पालकी यात्रा की तैयारियों को लेकर उषाराजे परिसर पर आयोजित बैठक में कही। ताई ने कहा कि इस यात्रा में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी शामिल होंगे तथा वे अपने करकमलों से देवी की प्रतिमा को पालकी में विराजित करेंगे। इस यात्रा में पूरे शहर का प्रतिनिधित्व हो ऐसा प्रयास हमें करना चाहिए। इसके लिए हमारे कार्यकर्ता शहर के हर समाज एवं व्यापारिक संस्थाओं से संपर्क करें एवं उन्हें इस पालकी यात्रा में शामिल होने का निवेदन करें। मुख्य संयोजक सांसद शंकर लालवानी ने सभी कार्यकताओं के साथ व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि - इस यात्रा में कई सामाजिक संगठन विशेष झांकियां लगाएंगे। कई भजन गायक लगातार भजन गाते हुए साथ चलेंगे। माइक भी शाम को ही शुरू होंगे एवं एमजी रोड पर सड़क के एक तरफ स्वागत मंच लगेंगे। संस्था के कार्यवाहक अध्यक्ष अशोक डागा ने बताया कि 1 सितम्बर को अहिल्याबाई की 229वीं पुण्यतिथि है। सुबह 8 अहिल्या प्रतिमा पर माल्यार्पण व इन्द्रेश्वर महादेव मंदिर में रुद्राभिषेक संपन्न होगा। मीडिया प्रभारी राम मूंदड़ा ने बताया कि बैठक में ग्रामीण प्रतिनिधि देवराजसिंह परिहार, बेटमा से सचिन गोरे, डॉ.डी.पी. मिश्रा, कम्पेल से संतोष पटेल, गौतमपुरा से विशाल राठी, देपालपुर से अनिल सोलंकी, पार्षद बरखा मालू, शिखा दुबे, प्रशांत बडवे, योगेश गेंदर, सुरेश टाकलकर, कंचन गिडवानी, राजा मंगवानी, कमल आहूजा सहित सिंधी समाज के वरिष्ठजन उपस्थित थे। बैठक में मुख्य रूप से सुधीर देडगे, रविंद्रसिंह गौड़, प्रेमप्रकाश वर्मा, कंचन गिदवानी, ज्योति तोमर, कमलेश नाचन, सुधीर दांडेकर, प्रकाश पारवानी, देवेंद्र ईनाणी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन शरयू वाघमारे ने किया एवं उत्सव प्रमुख सुधीर देड़गे ने आभार माना।

नालों पर घर बन गए, इसलिए इंदौर में भर रहा बारिश का पानी, हटेंगे कब्जे

इंदौर। पिछले सप्ताह बारिश के बाद इंदौर में हुए जल भराव ने सभी जगह शहर की व्यवस्थाओं की किरकिरी की। इसके बाद मुख्यमंत्री ने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की बैठक ली। इसके बाद स्पष्ट निर्देश दिए कि अब इंदौर को इस तरह का कोई दृश्य देखना न पड़े। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद प्रशासन इस मामले में सक्रिय हो गया है और अब जमीनी स्तर पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। बुधवार को कलेक्टर आशीष सिंह ने नालों पर अतिक्रमण की जांच करवाई। इस दौरान कई जगह प्रशासन की टीम को अतिक्रमण मिले। एसडीएम घनश्याम धनगर के नेतृत्व में राजस्व, नगर निगम के संयुक्त दल मैदान में निकले। एसडीएम घनश्याम धनगर ने निरीक्षण के बाद बताया कि नालों पर हो रहे अतिक्रमण की वजह से जल भराव की स्थिति बनती है। नालों को ब्लॉक करने और अवरोध पैदा करने के कई उदहारण मिले हैं। कई जगह पर लोगों ने नालों को ब्लॉक कर घर तक बना लिए हैं। धनगर ने कहा कि प्रशासन अपनी निरीक्षण रिपोर्ट कलेक्टर को प्रस्तुत करेगा। इसके बाद नालों का अवरोध हटाने को कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा कि हमने कई जगह चिन्हित की हैं। इसमें हमें नालों पर अतिक्रमण की जानकारी मिली है। कई जगह नालों को पूरी तरह से बंद भी कर दिया गया है। टीम को निर्देश दिए हैं कि इन सभी जगह पर जल्द ही अतिक्रमण हटाकर रास्ता बनाएं और पानी के निकलने की जगह तैयार करें ताकि जल भराव की स्थिति न बने।

सफाईकर्मी रहे अवकाश पर, मेयर, कलेक्टर, कमिश्नर ने लगाई झाड़ू

इंदौर। इंदौर में गोगादेव नवमी पर नगर निगम के आठ हजार से ज्यादा सफाईकर्मी अवकाश पर रहे,लेकिन शहर में इसका असर नहीं दिखा। शहरवासियों ने खुद सड़कों से झाड़ू लगाई, गंदगी उठाई और शहर की सफाई बरकरार रखी। मेयर, कलेक्टर, कमिश्नर से लेकर कर्मचारियों ने पूरी शिद्दत से सड़कों पर झाड़ू लगाई। मेयर ने राजवाड़ा पर महालक्ष्मी की बेकलेन से गंदगी उठाई। कलेक्टर ने उस मंच की सफाई की, जहां वाल्मीकि समाज ने जुलूस का स्वागत किया था। सफाई के बाद सभी ने राजवाड़ा पर पोहे खाए। दो घंटे पूरे शहर में सफाई अभियान चला। इसके बाद शहर रोज की तरह साफ नजर आया,हालांकि कई इलाकों में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन की गाड़ियां जरुर नहीं आई, लेकिन लोगों ने कचरा सड़कों पर नहीं फेंका, बल्कि आंगन में ही संभाल कर रखा। प्रमुख मार्गों की सफाई के लिए नगर निगम ने वैकल्पिक व्यवस्था की थी। मंगलवार रात को ही सड़कों पर मशीनों से साफ किया गया था। गलियों में रहवासियों ने झाड़ू लगाकर कचरा उठाया। मेयर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि इंदौर की स्वच्छता की सबसे बड़ी ताकत जनभागीदारी है।

ओडिशा, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, उत्तरप्रदेश और बिहार से जुड़े साइबर ठगों के तार

आठ माह में 13 लोग हुए 'डिजिटल अरेस्ट' के हुए शिकार

सिटी चीफ इंदौर।

इंदौर। शहर में साइबर अपराधियों द्वारा लोगों को हाउस अरेस्ट कर ठगने के मामले तेजी से सामने आ रहे हैं। पिछले आठ महीनों के दौरान ठग गिरोहों ने ऐसे अलग-अलग मामलों में 13 लोगों को कुल 1.50 करोड़ रुपए का चूना लगाया है। पुलिस ने बताया कि डिजिटल अरेस्ट साइबर ठगी का नया तरीका है। ऐसे मामलों में ठग खुद को कानून प्रवर्तन अधिकारी बताकर लोगों को ऑडियो या वीडियो कॉल करके डराते हैं और उन्हें उनके घर में डिजिटल तौर पर बंधक बना लेते हैं। एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया के मुताबिक हमें एक जनवरी से अब तक डिजिटल अरेस्ट के नाम पर कुल 1.50 करोड़ रुपए की ठगी को लेकर 13 लोगों की शिकायतें मिली हैं। इसमें से 46 लाख रुपए की रकम हमने पीड़ितों को वापस करा दी है। डिजिटल अरेस्ट के अधिकतर मामलों में ठगों ने खुद को पुलिस या सीमा शुल्क विभाग के अधिकारी या कोरियर कंपनी के कर्मचारी बताया और मनगढ़ंत मामलों में कानूनी कार्रवाई का डर दिखाकर शिकायतकर्ताओं को ऑनलाइन ठग लिया। एडिशनल डीसीपी के मुताबिक जांच में पता चला है कि डिजिटल अरेस्ट के नाम पर ठगी की वारदातों को अंजाम देने वाले लोगों के तार ओडिशा, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, उत्तरप्रदेश और बिहार से जुड़े हैं। शहर में डिजिटल अरेस्ट के ताजा मामले में ट्रांसफार्मर

बनाने वाले एक कारखाने के मालिक को जाल में फंसा कर आठ लाख रुपए का चूना लगा दिया गया। ठगों ने इस व्यक्ति को फोन करके कहा कि उसके द्वारा थाईलैंड भेजे गए कंटेनर में नशीली दवाएं और आपत्तिजनक सामग्री मिलने के कारण सीमा शुल्क विभाग ने कंटेनर जब्त कर लिया है। एडिशनल डीसीपी दंडोतिया के मुताबिक ठगों ने कारखाने के मालिक को यह झांसा भी दिया कि उसका बैंक खाता अंतरराष्ट्रीय स्तर पर धनशोधन में इस्तेमाल हुआ है। ठगों ने खुद को मुंबई पुलिस की अपराध निरोधक शाखा के अधिकारी बताकर जांच के नाम पर इस व्यक्ति को वीडियो कॉल किया। उन्होंने इस व्यक्ति को 14 साल के कारावास और भारी जुर्माने का डर दिखाकर उसके बैंक खाते से एक अन्य खाते में आठ लाख रुपए की रकम मंगवा ली। वीडियो कॉल के दौरान जब दूसरी तरफ से बहुत देर तक कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, तो कारखाने के मालिक को अहसास हुआ कि उसे चूना लगा दिया गया है।

हाईकोर्ट एडवोकेट के साथ भी हो गई ठगी

इंदौर के एरोड्रम पुलिस ने हाईकोर्ट एडवोकेट के साथ हुई ठगी के मामले में धोखाधड़ी की धाराओं मे केस दर्ज किया है। बताया जाता है कि आरोपी ने लिंक भेजकर उसे क्लिक करने के लिए कहा। जिस पर क्लिक करने के बाद मोबाइल का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर आरोपी ने वकील के क्रेडिट कार्ड अकाउंट से करीब 51 हजार रुपए निकाल लिए। एरोड्रम पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक विस्मित पनौत निवासी अशोक नगर की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात मोबाइल कस्टमर के खिलाफ 318 (4) बीएनएस को लेकर केस दर्ज किया है। विस्मित ने पुलिस को की गई शिकायत में बताया कि वह हाईकोर्ट एडवोकेट है। 2 अगस्त 2024 को उनके पास एक नंबर से कॉल आया। बात करने वाले वन कार्ड क्रेडिट कार्ड कंपनी का एजेंट बताया। पुरानी शिकायत के निवारण को लेकर विस्मित के ई मेल आईडी से खुद ईमेल आईडी पर एक लिंक भेजी। उसे खोलने के बाद विस्मित को दूसरी लिंक भेजी गई। उसे ओपन करते ही गूगल मीट के माध्यम से एडवोकेट के मोबाइल का कंट्रोल खुद करने लगा। क्रेडिट कार्ड से धोखाधड़ी करते हुए 51 हजार से अधिक की अमाउंट का ट्रांजैक्शन कर लिया। विस्मित के मोबाइल पर उक्त राशि को लेकर मैसेज आया। उन्होंने समझदारी दिखाते हुए तुंरत कॉल काट दिया। इसके बाद क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक करवा दिया। उन्होंने मामले की साइबर सेल में शिकायत भी कर दी। जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की है।

मेट्रो के अधिकारी को 48 घंटे तक किया था हाउस अरेस्ट

दो हफ्ते पहले इंदौर में मेट्रो रेल कार्पोरेशन कंपनी में पदस्थ एक अधिकारी को 48 घंटे तक हाउस अरेस्ट कर साइबर अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान दो लाख रुपए ठग लिए। स्काइप एप के माध्यम से संपर्क कर अपराधियों ने खुद को मुंबई क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताया। उन्होंने कहा कि आपके आधार नंबर पर जारी मोबाइल सिम का उपयोग ड्रग्स ट्रैफिकिंग में हुआ है। आपके खाते में भी एक लाख रुपये जमा हुए हैं। ऐसे में अब सीबीआई भी आप पर निगरानी कर रही है। आप किसी से बात न करें, नहीं तो पुलिस आपको अरेस्ट कर लेगी। ऐसा कहकर अपराधियों ने 12 अगस्त को यूपीआई के माध्यम से 99 हजार रुपये व 13 अगस्त को भी 99 हजार रुपये जमा करवाए। अपराधियों ने मेट्रो के अधिकारी से उनके बैंक खातों की जानकारी भी मांगी। अपराधियों के झांसे में आकर उन्होंने सारी जानकारी भी उन्हें उपलब्ध करवाई है। इस मामले में मेट्रो के अधिकारी ने क्राइम ब्रांच के अधिकारियों को शिकायत की।

डर, लालच और लापरवाही... तीन बड़े कारण

राज्य सायबर सेल में पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह के मुताबिक डिजिटल अरेस्ट के तीन प्रमुख कारण अभी तक सामने आए हैं। पहला है डर, दूसरा है लालच और तीसरा है लापरवाही। जितेंद्र सिंह के मुताबिक तुरंत पुलिस में शिकायत करने से पैसा वापस मिल जाने की उम्मीद रहती है। भारत के बैंक अकाउंट में ही अधिकतर मामलों का पैसा रहता है। यदि पीड़ित तुरंत शिकायत कर दे तो पैसे को बैंक से निकलने से रोका जा सकता है। इस तरह की किसी भी घटना पर तुरंत 1930 पर फोन करें।

वार्ड 83 का उप चुनावः लोकसभा चुनाव में 'बम कांड' से कांग्रेस ने लिया सबक

पार्षद चुनाव में कांग्रेस ने दो प्रत्याशियों से भरवाए नामांकन

सिटी चीफ इंदौर।

इंदौर। इंदौर में वार्ड क्रमांक 83 का पार्षद पद रिक्त है। यहां उप चुनाव हो रहे हैं। इसके लिए नामांकन भरने का बुधवार आखिरी दिन था। बुधवार को सात प्रत्याशियों द्वारा नामांकन भरा गया। कांग्रेस ने इस बार अपने डमी प्रत्याशी को कांग्रेस के मुख्य प्रत्याशी के साथ मैदान में सक्रिय बनाए रखने का भी प्लान बनाया है। लोकसभा चुनाव में भाजपा ने कांग्रेस के अक्षय कांति बम का जो नाम वापस करवाया था, उससे इस बार कांग्रेस ने सबक ले लिया है। यदि इस बार कांग्रेस का प्रत्याशी किसी कारणवश आखिरी में चुनाव से अपना नाम वापस ले लेगा तो उसकी जगह कांग्रेस का डमी प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा और कांग्रेस चुनाव में प्रत्याशी विहीन नहीं होगी। कांग्रेस ने इस बार विकास जोशी को अपना प्रत्याशी बनाया है और कांग्रेस के डमी प्रत्याशी के रूप में संजय पप्पू मालवीय को खड़ा किया है। बुधवार को विकास जोशी (इंडियन नेशनल कांग्रेस), संजय मालवीय (इंडियन नेशनल कांग्रेस), जितेंद्र राठौर (भारतीय जनता पार्टी), योगेंद्र मौर्य (निर्दलीय), पारस जैन (आम आदमी पार्टी), पूजा साहनी (बहुजन समाज पार्टी) तथा विनोद सिंह सूर्यवंशी (निर्दलीय) नामांकन पत्र दाखिल किए।

कांग्रेस का फुल प्रुफ प्लान

कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव की तरह डमी प्रत्याशी उतारा है लेकिन इस बार रणनीति बदली है। इस बार कांग्रेस ने डमी प्रत्याशी को कांग्रेस के साथ निर्दलीय के तौर पर भी मैदान में बनाए रखने का फुल प्रुफ प्लान बनाया है। दरअसल, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने अक्षय बम को अधिकृत प्रत्याशी बनाया था और फॉर्म बी पर डमी प्रत्याशी के रूप में मोतीसिंह पटेल का नाम दिया था। स्क्रूटनी में फॉर्म-बी नहीं होने से डमी प्रत्याशी पटेल का नामांकन खारिज हो गया था। इसी बीच, अधिकृत प्रत्याशी अक्षय बम ने भी फॉर्म उठा लिया। ऐसे में स्थिति यह बन गई कि कांग्रेस के पास कोई प्रत्याशी ही नहीं बचा। कांग्रेस के डमी प्रत्याशी संजय पप्पू मालवीय एक के बजाय 10 प्रस्तावक/समर्थकों के साथ फॉर्म भरने पर दिलचस्प जवाब दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने कांग्रेस पार्टी की तरफ से वार्ड 83 के उप-चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया है। कहीं लोकसभा चुनाव से सबक लेकर कांग्रेस डमी उम्मीदवार तो नहीं उतार रहीं, इस पर मालवीय का कहना है कि हां संभवतः यहीं बात है। आजकल स्थिति ऐसी है की छांछ को भी फूंक फूंक पर पीना पड़ रहा है। इसलिए पार्टी सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए काम कर रही है।

कांग्रेस प्रत्याशी विकास जोशी बोले- कांग्रेस ने मुझ पर विश्वास जताया

अधिकृत कांग्रेस प्रत्याशी विकास जोशी का कहना है कि मैंने अधिकृत प्रत्याशी के तौर पर फॉर्म भरा है, मालवीय पार्टी के डमी उम्मीदवार है। जब उनसे पूछा कि पार्टी ने दो उम्मीदवार से नामांकन भरवाया है, कहीं इस बार भी लोकसभा चुनाव जैसा तो कांग्रेस को डर नहीं है? विकास जोशी ने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए यह तो संगठन का काम है। संगठन नियमानुसार अपने दो प्रत्याशी खड़े करते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस ने मुझ पर विश्वास जताया है।

अब ऐसी गलती नहीं करना चाहती कांग्रेस

कांग्रेस सूत्रों ने बताया इस बार पार्षद उपचुनाव के लिए विकास जोशी को अधिकृत प्रत्याशी बनाया है और फॉर्म बी उनके नाम जारी किया है। उनके साथ संजय पप्पू मालवीय का भी डमी फॉर्म भरवाया है। अक्षय बम वाली स्थिति न बने इसलिए कांग्रेस ने संजय पप्पू मालवीय के नामांकन फॉर्म के साथ एक नहीं, बल्कि 10 समर्थकों का पत्र भी लगाया है। नियमानुसार, किसी भी राष्ट्रीय राजनीतिक दल के प्रत्याशी को मात्र एक प्रस्तावक की आवश्यकता होती है लेकिन कांग्रेस ने निर्दलीय की तरह आवश्यक एक प्रस्तावक और 10 समर्थकों के साइन कराए हैं।

इसकी वजह यह है कि यदि किसी कारण से दोनों में किसी का भी नामांकन खारिज होता है या फॉर्म बी समय पर नहीं पहुंचा तो उस स्थिति में यही कांग्रेस उम्मीदवार, बतौर निर्दलीय लड़ पाएंगे। यानी कांग्रेस निर्दलीय प्रत्याशी का समर्थन करके भी चुनाव लड़ सकेगी।

31 अगस्त तक नाम वापस ले सकते हैं नेता

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्राप्त नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा (जांच) 29 अगस्त को प्रातः 10:30 बजे से कक्ष क्रमांक 101 (न्यायालय कक्ष) कलेक्टर कार्यालय इंदौर में की जाएगी। नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 31 अगस्त 2024 तक रहेगी। नाम निर्देशन पत्र उक्त अवधि में दोपहर 03 बजे तक वापस लिए जा सकेंगे। चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची चुनाव चिन्ह के आवंटन का कार्य 31 अगस्त 2024 को ही अभ्यर्थिता से नाम वापसी के ठीक बाद होगा।

11 सितंबर को होगा मतदान

चुनाव के लिए मतदान 11 सितंबर बुधवार को प्रातः 07 बजे से अपरान्ह 05 बजे तक होगा। मतगणना और निर्वाचन परिणामों की घोषणा 13 सितंबर 2024 को प्रातः 09 बजे से जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम इंदौर में होगी।

बारिश थमते ही सड़कों पर दिखने लगे गड्ढे, पैचवर्क के लिए करना होगा इंतजार

सिटी चीफ इंदौर।

इंदौर। इंदौर में जलजमाव के बाद अब सड़कों पर हो रहे गड्ढे अब ट्रैफिक में बाधा खड़ी कर रहे है। इससे हादसे भी हो रहे है। बारिश का मौसम होने के कारण डामर प्लांट शुरू नहीं हो पाए है। इस कारण पेचवर्क भी नहीं हो पा रहे है। रिंग रोड के सर्विस रोड पर तो आधा से एक फुट के गड्ढे हो चुके है। मंगलवार को तिलक नगर रोड पर एक रिक्शा अचानक पलट गया था। बताया जा रहा है कि गड्ढे से बचने के लिए चालक ने रिक्शा डिवाइडर से टकर दी। इस हादसे में एक स्कूली बच्चे की मौत हो गई। डामर की सड़कों के अलावा सीमेंट की सड़कों पर भी गड्ढे नजर आने लगे है। शहर के आंबेडकर नगर, खजराना, विजय नगर, बाणगंगा, सदरबाजार सहित अन्य मार्गों पर गड्ढे हो चुके है। फिलहाल गहरे गड्ढों में निगम चूरी बिछा रहा है। मौसम खुलने के बाद पेचवर्क शुरू किया जाएगा।

सबसे ज्यादा गड्ढे पूर्वी रिंग रोड पर

इंदौर में सबसे ज्यादा गड्ढे पूर्वी रिंग रोड पर है। यहां खजराना और मुसाखेड़ी में ब्रिज का काम चल रहा है। ट्रैफिक का दबाव सर्विस रोड पर है, लेकिन वहां आधे फीट के गड्ढे हो चुके है। खजराना चौराहे पर इस कारण यातायात भी बाधित हो रहा है। शहर के राऊ और स्वदेशी मिल ब्रिज पर भी गड्ढे हो चुके है और सरिए निकल आए है। बायपास से इंदौर की तरफ आने के लिए स्कीम-134 की कॉलोनियों में ट्रैफिक डायवर्ट किया गया है। इस कारण कॉलोनी की सड़कें खराब हो गई है।

बारिश थमने के बाद ही होगा पैचवर्क

शहर की सड़कों पर गड्?ढों के स्थायी समाधान का दावा बारिश बाद किया जा रहा है। हालांकि तब तक अस्थायी पैचवर्क से काम चलाया जाएगा। महापौर पुष्यमित्र भार्गव का कहना है कि बारिश थमते ही 45 दिन में पैचवर्क शुरू किया जाएगा। इसके लिए टेंडर हो चुके हैं। एजेंसी भी फाइनल की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि सीमेंट कांक्रीट की सड़कों पर बारिश के दौरान ही पैचवर्क करवाया जाएगा। इसके लिए 1 करोड़ की लागत से टेंडर जारी किया गया है। सुगम यातायात के लिए ट्रैफिक पुलिस, नेशनल हाईवे, आईडीए या एमपीआरडीसी की मदद लेंगे।

खराब सड़कों के कारण एक हजार से ज्यादा हादसे

शहर में बीते छह माह में ट्रैफिक विभाग के अनुसार 1850 से ज्यादा हादसे हुए है। इनमें एक हजार से ज्यादा हादसे खराब सड़कों के कारण हुए है। सड़क हादसों के कारण छह माह में 150 मौतें हो चुकी है। जनकार्य समिति प्रभारी राजेंद्र राठौर ने कहा कि पेचवर्क के टेंडर आमंत्रित किए है।

इंदौर जिले में अब तक 25 इंच बारिश, पिछले साल के मुकाबले 4 इंच कम

सिटी चीफ इंदौर।

इंदौर। इंदौर जिले में जारी मानसून सत्र में अब तक लगभग 633 मिली मीटर (25 इंच) औसत वर्षा दर्ज की गई है। यह गत वर्ष इस अवधि में दर्ज वर्षा से लगभग 100 मिलीमीटर (4 इंच) कम है। गत वर्ष इस अवधि में जिले में 733 मिली मीटर (29 इंच) वर्षा हुई थी। भू-अभिलेख कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस वर्ष अब तक इंदौर क्षेत्र में 725.6 मिलीमीटर, महू में 486.1 मिलीमीटर, सांवेर में 697.5 मिलीमीटर, देपालपुर में 753 मिलीमीटर, गौतमपुरा क्षेत्र में 635.7 मिलीमीटर तथा हातोद क्षेत्र में 498.8

मिलीमीटर वर्षा हुई है। जिले में गत वर्ष अब तक इंदौर क्षेत्र में 628.9 मिलीमीटर, महू में 650 मिलीमीटर, सांवेर में 814.8 मिलीमीटर, देपालपुर में 1050.2 मिलीमीटर, गौतमपुरा क्षेत्र में 648 मिलीमीटर तथा हातोद क्षेत्र में 605.8 मिलीमीटर वर्षा हुई थी।

बुधवार को हुई हल्की बूंदाबांदी

इंदौर में बुधवार सुबह से मौसम खिला रहा। दोपहर 1 बजे के बाद शहर के पूर्वी और मध्य इलाके में बादल छाने के साथ हल्की बूंदाबांदी हुई। वहीं शहर में इस बार जून व जुलाई माह में औसत से बारिश भले ही कम हुई हो, लेकिन अगस्त माह में बारि?श का कोटा पूरा हो गया है। इंदौर में अब तक 28 इंच बारिश दर्ज की जा चुकी है। इंदौर में सीजन का कोटा 36 इंच का है। मंगलवार को शहर में सुबह बादल छंटने के बाद धूप खिली थी और शाम चार बजे बाद शहर के अलग-अलग हिस्सों में रुक-रुककर करीब सवा घंटे तक तेज बौछारें भी पड़ी थी। मंगलवार को शहर का तापमान 30.0 (+1) डिग्री और रात का तापमान 22.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था।

सिस्टम कमजोर होने से बारिश का रुख बदला

इंदौर में 3 दिन से एक्टिव बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम अब थोड़ा कमजोर पड़ गया है। उसी के चलते बुधवार को दोपहर बाद बादल छाने के साथ कई इलाकों में रिमझिम होकर बारिश रुक गई। हालांकि मौसम विभाग ने 29-30 अगस्त से फिर स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनने की घोषणा की है।

महिलाओं पर हो रहे अत्याचार, 33 प्रतिशत आरक्षण की मांग को लेकर किया प्रदर्शन, राज भवन जाने से पुलिस ने रोका

प्रदर्शन करते महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को आ गया चक्कर

सिटी चीफ भोपाल।
महिलाओं पर हो रहे अत्याचार, 33 प्रतिशत आरक्षण की मांग को लेकर प्रदेश महिला कांग्रेस ने भोपाल में प्रदर्शन किया। कार्यकर्ता राजभवन के लिए रवाना हुईं, लेकिन पुलिस ने रोक लिया। इस दौरान कांग्रेस महिला प्रदेश अध्यक्ष विभा पटेल का चक्कर आ गया।

मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रदर्शन के माध्यम से लगातार सरकार को घेर रही है। जहां कांग्रेस के सभी प्रकोष्ठ अलग-अलग प्रदर्शन कर मुद्दे उठा रहे हैं वहीं अब महिला मोर्चा भी सामने आ गया है। बुधवार को राजधानी भोपाल में कांग्रेस के नारी न्याय आंदोलन का दूसरा चरण शुरू हुआ। इस दौरान महिला कांग्रेस की सदस्यों ने भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर धरना-प्रदर्शन किया। इसमें पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा और महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष विभा पटेल शामिल हुईं। यहां से कार्यकर्ता राजभवन के लिए रवाना हुईं, लेकिन पुलिस ने उन्हें पहले ही रोक लिया। इस पर महिला नेताओं ने नारेबाजी शुरू कर दी। इस दौरान गर्मी की वजह से विभा पटेल को चक्कर आ गया। वे नीचे बैठ गईं।

मध्य प्रदेश में हर दिन होती है 17 रेप की घटनाएं
इस दौरान कांग्रेस की महिला प्रदेश अध्यक्ष विभा पटेल ने कहा कि महिला अत्याचार में मध्यप्रदेश पहले नंबर पर है। यहां हर दिन रेप की 17 घटनाएं सामने आती हैं। ऐसे में महिलाओं के लिए बने कानून को सख्ती से लागू करने की आवश्यकता है। अपराधियों में खौफ होना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं होता। पीड़ित को भटकना पड़ता है।।आर्थिक, सामाजिक और यौन उत्पीड़न, महिला आरक्षण, जातिगत जनगणना, बेलगाम महंगाई, चौपट स्वास्थ्य व्यवस्था जैसे कई मुद्दे हैं। हम यह भी चाहते हैं कि लाड़ली बहनों की लिस्ट से काटे गए नाम वापस जोड़े जाएं।

महिलाओं को 33त्न मिले आरक्षण
इस दौरान पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि महिलाओं को विधानसभा में 33 प्रतिशत आरक्षण मिलना चाहिए। ये घर चला सकती हैं तो राज्य और देश भी चला सकती हैं। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि हमें न्याय के लिए लड़ना है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने महिलाओं को 33त्न आरक्षण देने की बात कही थी। अब लोकसभा में महिलाओं को 33 प्रतिशच आरक्षण चाहिए। उन्होंने कहा कि आज देश में किसी महिला को न्याय की सबसे ज्यादा जरूरत है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पत्नी जसोदाबेन को है।

महिलाओं पर हो रहे अत्याचार, 33 प्रतिशत आरक्षण की मांग, महंगाई सहित अन्य मुद्दों को लेकर कांग्रेस सड़कों पर उतर आई है।गौरतलब है कि आजादी के दौरान चलाए गए अगस्त क्रांति आंदोलन की तर्ज पर कांग्रेस अगस्त महीने में लगातार आंदोलन और प्रदर्शन कर रही है। इसके तहत नारी न्याय आंदोलन का पहला चरण 29 जुलाई 2024 को दिल्ली के जंतर-मंतर से शुरू किया गया था।

सीएम ने ली समीक्षा बैठक, उज्जैन में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना के लिए केंद्र सरकार

नर्मदापुरम सहित पांच शहरों में खुलेंगे आयुर्वेदिक महाविद्यालय

सिटी चीफ भोपाल।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने घोषणा की है कि मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम, बालाघाट, सागर, शुजालपुर, और डिंडोरी में नए आयुर्वेदिक महाविद्यालय खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि आयुर्वेदिक शिक्षा के विस्तार के लिए निजी क्षेत्र को भी प्रोत्साहित किया जाएगा, खासकर जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों में आयुर्वेदिक महाविद्यालयों की स्थापना प्राथमिकता पर होगी। यह घोषणा मुख्यमंत्री ने मंत्रालय में आयोजित आयुष विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान की।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने खजुराहो में योग संस्थान की स्थापना के लिए केंद्र सरकार से निरंतर संपर्क बनाए रखने और प्रयास जारी रखने की बात कही। इसके साथ ही उन्होंने उज्जैन में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने बताया कि कोविड-19 महामारी के बाद आयुर्वेद का महत्व काफी बढ़ गया है। इस संदर्भ में उन्होंने आयुष विभाग से पैरा मेडिकल पाठ्यक्रमों की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया, जिससे उपचार और रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न हो सकें।

543 आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी की नियुक्ति प्रक्रिया जारी
बैठक में बताया गया कि आयुष विभाग में 332 पैरामेडिकल कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही 14 यूनानी चिकित्सा अधिकारियों और 36 होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारियों के नियुक्ति आदेश जारी किए गए हैं। लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित 543 आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति प्रक्रिया भी जारी है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर के अंतर्गत 533 संविदा चिकित्सा अधिकारियों (सीएएमओ) की पदस्थापना की गई है। इसके अलावा, सत्र 2023-24 में आयुर्वेद के दो नए विषयों, स्त्री रोग प्रसूति तंत्र (उज्जैन और भोपाल महाविद्यालय) और पंचकर्म (उज्जैन महाविद्यालय) में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम भी शुरू किए गए हैं।

पं. खुशीलाल शर्मा महाविद्यालय के सुदृढ़ीकरण के लिए राशि स्वीकृत
मुख्यमंत्री ने बताया कि भोपाल के पं. खुशीलाल शर्मा शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय के सुदृढ़ीकरण के लिए 1999.86 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। साथ ही, शासकीय स्वशासी यूनानी महाविद्यालय, भोपाल में 180 बिस्तरों वाले बालिका छात्रावास का संचालन किया जा रहा है। आयुष विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, पिछले साल ओपीडी और आईपीडी में एक करोड़ 37 लाख मरीजों का इलाज हुआ और 2,500 से अधिक रोगियों की शल्य चिकित्सा की गई। योगा वैलनेस केंद्रों में 9,600 सत्रों का आयोजन किया गया।

पचमढ़ी में पर्यटन विभाग की अभिनव पहल

मप्र में सिर्फ महिलाएं संचालित करेंगी होटल

भोपाल। प्रदेश के एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी में पर्यटन विकास निगम महिला सशक्तीकरण की दिशा में नई पहल करने जा रहा है। निगम की पचमढ़ी में स्थित इकाई होटल अमलतास के संचालन की कमान अब महिलाओं को सौंपी जा रही है। अक्टूबर माह से इसकी विधिवत शुरूआत होगी। होटल में कार्यरत पुरुष कर्मचारियों को दूसरे स्थान पर भेजा जाएगा।

महिलाओं को रोजगार देने और सुरक्षित पर्यटन के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की वुमन विंग के साथ मिलकर पर्यटन निगम यह प्रयोग कर रहा है। इसके लिए महिलाओं को होटल मैनेजमेंट का प्रशिक्षण दिया चुका है। संभवत- यह देश का पहला होटल होगा, जिसके संचालन की जिम्मेदारी महिलाओं के पास होगी।

यह प्रयोग सफल होने के बाद निगम अपनी अन्य इकाइयों व होटलों में भी महिलाओं को अवसर देगा।

इसी प्रकार प्रदेश में महिलाओं के लिए सुरक्षित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पचमढ़ी, मढ़ई और शिवपुरी में युवतियां गाइड का काम और सफारी वाहन का संचालन भी कर रही हैं।

युवतियां पर्यटकों को करा रहीं जंगल की सैर
मध्य प्रदेश पर्यटन द्वारा महिलाओं के रोजगार के लिए भी कई अभिनव पहल की जा रही हैं। महिलाओं के लिए सुरक्षित पर्यटन कार्यक्रम के अंतर्गत सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में आने वाले पचमढ़ी व मढ़ई में प्रशिक्षित युवतियों द्वारा गाइड और सफारी वाहन का संचालन किया जा रहा है। वहीं शिवपुरी के माधव नेशनल पार्क में भी फॉरेस्ट महिला गाइड हैं। यहां लगभग 20 स्थानीय प्रशिक्षित महिलाओं द्वारा पर्यटकों को जंगल की सैर कराई जा रही है। इसके माध्यम से महिलाओं के सशक्तीकरण का संदेश पूरे देश में जा रहा है।

पचमढ़ी स्थित पर्यटन विकास निगम के होटल नीलांबर के रेनोवेशन का काम भी पूरा हो चुका है। रेनोवेशन के चलते यह हेरिटेज होटल पिछले एक साल से बंद था। महिलाओं द्वारा होटल संचालन परियोजना और नीलांबर का उद्घाटन संभवत- एक साथ किया जा सकता है।

इनका कहना है
पर्यटन विभाग की ओर से पर्यटन के क्षेत्र में लगातार नवाचार किए जा रहे हैं। इसके माध्यम से महिलाओं को समान अवसर देते हुए मजबूत किया जा रहा है। होटल अमलतास में महिलाओं ने काम करना शुरू भी कर दिया है। अक्टूबर में उन्हें संचालन की पूर्ण जिम्मेदारी दे दी जाएगी।
-इलैयाराजा टी, एमडी, मप्र पर्यटन निगम

चार घंटे तक चला हंगामा, जाम से वाहन चालक हुए परेशान

बिजली कनेक्शन वैध करने मांगे एक लाख, सड़क पर उतरे रहवासी

सिटी चीफ भोपाल।
भोपाल। शहर के खेजड़ा बरामद इलाके में बिजली कनेक्शन को वैध करने के बदले में उपभोक्ताओं से एक लाख रुपये मांगे जा रहे थे। इस पर उपभोक्ता नाराज हो गए और उन्होंने सड़क पर उतरते हुए जमकर हंगामा कर दिया। इस दौरान रहवासियों ने मुख्य रास्तों तक को बंद कर दिया, जिससे लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ा।

वार्ड 74 स्थित खेजड़ा बरामद में दो दिन पहले शनिवार-रविवार को जलभराव की स्थिति निर्मित हो गई थी। यहां पर स्थित राधाकृष्णा, तिरुपति सिटी, पुण्यधाम, निकुंज धाम, पुष्पानंद सिटी आदि कालोनियां हैं। इनमें करीब 300 परिवार निवास करते हैं। खेजड़ा बरामद स्थित कॉलोनियों में निवास कर रहे लोगों के पास अस्थायी बिजली कनेक्शन हैं। इनको स्थायी करने की कार्रवाई करते हुए कंपनी सात किलोवाट तक का कनेक्शन दे रही है, जिसके बदले में 70 हजार से सवा लाख रुपये जमा करवाए जा रहे हैं।

कनेक्शन के 24 हजार रुपए मांगे
प्रतिभा सिटी में रहने वाले मुकेश साहू ने बताया कि उन्होंने कनेक्शन के लिए आवेदन किया था, जिसके बदले में उनसे एक लाख 24 हजार रुपये जमा करने के लिए कहा गया है। कंपनी की टीम मंगलवार को कनेक्शन काटने की कार्रवाई करने पहुंची थी। इससे रहवासी नाराज हो गए और महिला के साथ बच्चों भी सड़क पर उतर आए। करीब चार घंटे तक हंगामा किया, जिससे जाम की स्थिति निर्मित हो गई। इस विरोध के चलते टीम को वापस लौटना पड़ा। वहीं, कंपनी ने लोगों को कुछ दिन की मोहलत दी है। नाराज रहवासी क्षेत्रीय विधायक व मंत्री कृष्णा गौर से मिले और कहा कि वह नियमानुसार राशि जमा करेंगे।

पीसीसी चीफ ने सेवा दल से 6 महीने के काम का हिसाब मांगा, कल बैठक

कांग्रेस में काम के आधार पर मिलेगा पद

सिटी चीफ भोपाल।
मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी संगठन को मजबूत करने में जुटे हैं प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी का सीधे तौर पर निर्देश है कि जो काम करेगा उसी को पार्टी में जगह मिलेगी काम नहीं करने वालों को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। पटवारी सभी प्रकोष्ठों से अब काम का हिसाब मांगना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश कांग्रेस सेवादल की गुरुवार को पपीसीसी भोपाल में समीक्षा बैठक होने जा रही है। बुधवार को पीसीसी चीफ जीतू पटवारी दिल्ली में कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से मुलाकात कर आगामी संगठनात्मक रणनीति के संदर्भ में चर्चा की। जानकारी के अनुसार पटवारी प्रदेश में संगठन को लेकर चल रही गतिविधियों की जनकारी लेकर दिल्ली पहुंचे हैं।

इस बैठक के लिए सभी प्रदेश पदाधिकारियों के साथ ही जिला अध्यक्ष एवं ब्लॉक अध्यक्षों से उनके पिछले 6 महीनों के काम काज का हिसाब मांगा है। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के अलावा प्रदेश कांग्रेस के सह प्रभारी सीपी मित्तल, प्रदेश सेवादल के प्रभारी पीएन मिश्रा, सह प्रभारी सीपी गौतम भी विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। बैठक में सेवादल के सभी प्रदेश पदाधिकारी, जिला और ब्लॉक के अध्यक्षों को बुलाया गया है। बैठक में पिछले 6 महीने के कामकाज की समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा अगले एक साल के लिए विभिन्न कार्यक्रमों, कार्यशालाओं और आंदोलन की रूपरेखा तय की जाएगी।

फिर बादल की संभावना
इस बैठक के बाद सेवादल की प्रदेश कार्यकारिणी के साथ ही जिला और ब्लॉक में बड़ा फेरबदल होने की संभावना है। पिछले 6 महीने में काम काज के समीक्षा के जरिए हर पदाधिकारी के काम की समीक्षा होगी। जो पदाधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, उनकी छुट्टी की जाएगी। इस संबंध में बैठक के कुछ दिनों के भीतर ही एक रिपोर्ट तैयार होगी, जिसमें हर पदाधिकारी के काम काज को लेकर बताया जाएगा। जिसके आधार पर जल्द ही फेरबदल हो सकता है।

पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने पीएम और मप्र के सीएम से वीडियो जारी कर की अपील

2011 से नहीं बढ़े सोयाबीन के भाव, 6000 प्रति क्विंटल किए जाएं

सिटी चीफ भोपाल।
मध्य प्रदेश सोयाबीन के उत्पादन में देश में नंबर एक पर है। यहां देश का करीब 50 प्रतिशत सोयाबीन पैदा किया जाता है, लेकिन किसानों को सोयाबीन का सही दाम नहीं मिलने से किसानों ने नाराजगी है। किसानों के इस समस्या को लेकर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव से एक वीडियो जारी कर अपील की है कि सोयाबीन का रेट बढ़ाया जाए।

दिग्विजय सिंह ने कहा है कि 2011 के बाद से सोयाबीन के भाव लगभग स्थिर हैं। इसलिए किसानों के हित में सोयाबीन के दाम 6000 प्रति क्विंटल किए जाने चाहिए ताकि देश और एमपी के किसानों को सोयाबीन की फसल का पूरा लाभ मिल सके। पूर्व मुख्यमंत्री सिंह ने कहा है कि देश में लगभग 50त्न से अधिक सोयाबीन मध्यप्रदेश में पैदा की जाती है लेकिन सन 2011 से लेकर आज तक लागत दोगनी तिगुनी हो गई, लेकिन सोयाबीन का भाव जस का तस है। 4300 रुपए प्रति क्विंटल 2011 में था और अभी उसी के आस पास है। उन्होंने कहा कि सोयाबीन की फसल का भाव अंतर्राष्ट्रीय सोयाबीन के उत्पादन पर निर्भर करता है और इस साल जो संभावना है उसके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोयाबीन का भाव इसी प्रकार का रहेगा जो अभी तक 4000, 4300 रुपए प्रति क्विंटल बिकता था, शायद वह भी न मिल सके।

अधिकांश किसान खरीफ में सोयाबीन की फसल लेते
सिंह ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से अपील करता हूं कि चूंकि हमारे अधिकांश किसान खरीफ में सोयाबीन की फसल लेते हैं, इसलिए उसके उत्पादन की खरीद सरकार को अवश्य करना चाहिए। उन्होंने मांग की है कि इसका न्यूनतम भाव आज की लागत को देखते हुए लगभग 6000 क्विंटल से कम नहीं होना चाहिए।

यही मध्यप्रदेश के 100त्न किसानों की डिमांड भी है, इस बात पर पीएम और सीएम पूरा ध्यान दें।

सम्पादकीय

भारतीयों के जीवन के 51 दिन बढ़े...अभी और काम करने की जरूरत

साल 2021 की तुलना में 2022 में भारत में कणीय प्रदूषण में 19.3 प्रतिशत की महत्वपूर्ण गिरावट की वजह से देश के नागरिकों की जीवन प्रत्याशा में 51 दिनों की बढ़ोतरी हुई है। अगर ग्रामीण भारत में खाना पकाने के लिए लकड़ी और कोयले की जगह एलपीजी का इस्तेमाल किया जाए तो हर साल 1,50,000 से ज्यादा लोगों की जान बच सकती है। इस बदलाव का सबसे ज्यादा फायदा उत्तरप्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और मध्यप्रदेश जैसे चार राज्यों को होगा।

भारत में प्रदूषण के एक बड़ी समस्या बनकर उभरा है। अब एक नई रिपोर्ट में जो दावा किया गया है, उससे हम भारतीयों को राहत जरूर मिलेगी। दरअसल एक रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2021 की तुलना में 2022 में भारत में कणीय प्रदूषण में 19.3 प्रतिशत की महत्वपूर्ण गिरावट दर्ज की गई है। यह बांग्लादेश के बाद दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी कमी है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि प्रदूषण में इस कमी से देश के नागरिकों की जीवन प्रत्याशा में 51 दिनों की बढ़ोतरी हुई है।

शिकागो विश्वविद्यालय (ईपीआईसी) में ऊर्जा नीति संस्थान द्वारा 'वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक-2024' शीर्षक से वार्षिक रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अगर भारत, विश्व स्वास्थ्य संगठन के वार्षिक पीएम 2.5 सांद्रता मानक 5 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर को पूरा करने में विफल रहता है, तो भारतीयों की जीवन प्रत्याशा में 3.6 वर्ष की कमी आने की आशंका है। शोधकर्ताओं ने भारत और अन्य दक्षिण एशियाई देशों में कणीय प्रदूषण में गिरावट का श्रेय मुख्य रूप से अनुकूल मौसम संबंधी परिस्थितियों को दिया है। देश में इन दिनों जमकर बारिश हो रही है, जिसके चलते भी प्रदूषण में गिरावट आई है। रिपोर्ट के अनुसार, भारत में साल 2022 में पीएम 2.5 सांद्रता लगभग 9 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर थी, जो 2021 की तुलना में 19.3 प्रतिशत कम है। कणीय प्रदूषण में सबसे बड़ी गिरावट पश्चिम बंगाल के पुरुलिया और बांकुरा जिलों में देखी गई, इसके बाद झारखंड के धनबाद, पूर्वी, पश्चिम सिंहभूम और बोकारो जिले हैं। इनमें से प्रत्येक जिले में, पीएम 2.5 सांद्रता में 20 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से अधिक की गिरावट आई। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के सबसे प्रदूषित क्षेत्र उत्तरी मैदानों में 2021 की तुलना में 2022 में कणीय प्रदूषण के स्तर में 17.2 प्रतिशत की कमी देखी गई। हालांकि, इस सुधार के बावजूद, अगर मौजूदा प्रदूषण स्तर जारी रहता है, तो इससे लोगों के औसत जीवन में अभी भी लगभग 5.4 वर्ष की कमी आने की संभावना है। दूसरी ओर, अगर आने वाले वर्षों में कणीय प्रदूषण के स्तर में गिरावट इसी दर से जारी रहती है, तो उत्तरी मैदानों में जीवन प्रत्याशा 1.2 वर्ष बढ़ सकती है। रिपोर्ट में बताया गया है कि साल 2019 में गुजरात में प्रदूषण की रोकथाम की पहल शुरू की थी। इसका असर दिखने लगा है और सूरत में प्रदूषण को 20-30 प्रतिशत तक कम कर दिया गया है। शोधकर्ताओं ने कहा कि इस प्रकार की अभिनव नीतियां दिखाती हैं कि आर्थिक विकास को अनावश्यक रूप से बाधित किए बिना भी वायु गुणवत्ता और लोगों के स्वास्थ्य में सुधार हासिल करना संभव है। रिपोर्ट में भारत सरकार की योजना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की भी प्रशंसा की गई है, जिसमें कहा गया है कि भारत में आवासीय क्षेत्र से उत्सर्जन में कमी का श्रेय काफी हद तक इस योजना के राष्ट्रव्यापी रोलआउट को दिया जा सकता है। इसने परिवहन से संबंधित उत्सर्जन में कमी का श्रेय परिवहन क्षेत्र में डीजल के कम उपयोग को दिया। यहां एक बात गौर करने वाली है कि उज्वला योजना के बावजूद आज भी गांव के लोग चूल्हें की रोटी खाना पसंद करते हैं और कई घरों में अभी भी लकड़ी और कोयले का इस्तेमाल किया जाता है। इसी बीच वाइटल स्ट्रेटेजीज नामक एक संस्था ने स्टडी की है। जिसमें बताया गया कि अगर ग्रामीण भारत में खाना पकाने के लिए लकड़ी और कोयले की जगह एलपीजी का इस्तेमाल किया जाए तो हर साल 1,50,000 से ज्यादा लोगों की जान बच सकती है। इसके साथ ही इस बदलाव से लोगों को 37 लाख साल ज्यादा स्वस्थ जीवन भी मिल सकेगा। भारत में बहुत से ग्रामीण परिवार अभी भी खाना पकाने के लिए लकड़ी, उपले और कोयले का इस्तेमाल करते हैं। इससे निकलने वाला धुआं सेहत के लिए बहुत हानिकारक होता है। वाइटल स्ट्रेटेजीज ने अपने सर्वे में पाया कि अगर ये परिवार पूरी तरह से एलपीजी अपना लें, तो इससे घर के अंदर और बाहर के प्रदूषण में कमी आएगी और हर साल 1,50,000 से ज्यादा लोगों की जान बच पाएगी। एलपीजी एक साफ-सुथरा ईंधन है। अध्ययन में यह भी पाया गया कि इस बदलाव का सबसे ज्यादा फायदा उत्तरप्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और मध्यप्रदेश जैसे चार राज्यों को होगा। इन राज्यों में आबादी ज्यादा है, एलपीजी का इस्तेमाल कम होता है और हवा में प्रदूषण का स्तर बहुत ज्यादा है। अध्ययन में बताया गया है कि एलपीजी के इस्तेमाल से होने वाले ज्यादा फायदा शिशु मृत्यु दर में कमी के रुप में दिखाई देगा। इससे पाच साल से कम उम्र के बच्चों का जन्म के समय वजन कम होने की समस्या भी कम होगी और 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों में सांस की बीमारियां भी कम होंगी। स्वास्थ्य शोधकर्ता मानते हैं कि भारत की वायु प्रदूषण समस्या को सुलझाने के लिए 'चूल्हे' के धुएं को कम करना बहुत जरूरी है।

'कंगना कल्चर' के अपने ही नेताओं से परेशान भाजपा

बेशक, राजनीति में बेबाकी भी एक व्यक्तिगत गुण है, लेकिन बेबाकी और अविवेकी होने में बुनियादी फर्क है। अगर बगैर राजनीतिक समझ के कोई सार्वजनिक बयान दिया जाता है तो यह या तो मूर्खता है या फिर उद्दंडता। बिना सोचे समझे सिर्फ सुर्खियां पाने के लिए कुछ भी कह देना खुद अपने और अपनी पार्टी के पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है।

बीते छह माह में संविधान, आरक्षण, जातिगत गणना और किसान आंदोलन के मुद्दे भाजपा की ऐसी दुखती रग बन गए हैं कि वो उसे कहां और कैसे राजनीतिक नुकसान पहुंचाएंगे, इसका अंदाजा भाजपा भी ठीक-ठीक नहीं लगा पा रही है। इनमें भी लंबे किसान आंदोलन के चलते तीन विवादित कृषि कानून मोदी सरकार द्वारा वापस ले लिए जाने के बाद यह मामला पिछले कुछ समय से हाशिये पर चला गया था, लेकिन भाजपा सांसद और बड़बोली अभिनेत्री कंगना रनौत ने इन हरियाणा विधानसभा चुनाव के पहले फिर इस मुद्दे को कुरेद कर भारतीय जनता पार्टी के लिए नई मुसीबत खड़ी कर दी है। लगता है पार्टी को अब अपने ही नेताओं के ऐसे घर जलाऊ बयानों पर पानी डालने के लिए अलग से फायर ब्रिगेड रखनी पड़ेगी। दूसरे शब्दों में कहें तो पार्टी में कंगना जैसे नेता हो तो दुश्मनों की जरूरत ही नहीं है। एक समय तक कांग्रेस मणिशंकर अय्यर, सैम पित्रोदा जैसे बड़बोले नेताओं से परेशान थी। लेकिन अब लगता है यह काम भाजपा में भी कुछ लोगों ने अपने हाथ में ले लिया है। भाजपा की बेबसी यह है कि वह इन मुद्दों पर लगातार नुकसान झेल रही है, लेकिन इसका कोई तोड़ या ठोस जवाब उसके पास नहीं है। यहां तक कि ऐसे नेताओं के खिलाफ वह कोई प्रभावी कार्रवाई भी नहीं कर पाती। इसके पीछे कारण या तो असहायता है या फिर खुद ऐसे लोगों को पार्टी की शह है। बेशक, राजनीति में बेबाकी भी एक व्यक्तिगत गुण है, लेकिन बेबाकी और अविवेकी होने में बुनियादी फर्क है। अगर बगैर राजनीतिक समझ के कोई सार्वजनिक बयान दिया जाता है तो यह या तो मूर्खता है या फिर उद्दंडता। बिना सोचे समझे सिर्फ सुर्खियां पाने के लिए कुछ भी कह देना खुद अपने और अपनी पार्टी के पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है।

वैसे भी कंगना रनौत ऐसे ही विवादित बयानों के लिए जानी जाती हैं। वे बेहतर अभिनेत्री हैं, लेकिन उनकी राजनीतिक और सामाजिक समझ भी उतनी ही परिपक्व हो, जरूरी नहीं है। वरना कोई कारण नहीं था कि हरियाणा विस चुनाव के ऐन पहले काफी हद तक ठंडे पड़ चुके किसान आंदोलन को बुरे लफ्जों में कोसा जाता।

कंगना के बयान के बाद हरियाणा में नाराज किसानों के प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। हैरानी की बात यह है कि कंगना ने ऐसा बयान तब दिया है कि जब वो इसी मुद्दे पर सीआईएसफ की एक महिला कांस्टेबल के हाथों सरेआम थप्पड़ खा चुकी हैं।

किसान आंदोलन कितना जायज, तार्किक और राजनीति से प्रेरित था, इसके पीछे किन ताकतों का हाथ था, इस पर बहस हो सकती है, लेकिन उसे अलगाववादियो और विदेशी हाथों से संचालित होने के आरोप लगाना और वो भी इस समय, राजनीतिक बुद्धिमानी कतई नहीं है। अगर यह साफगोई भी है तो उसमें समझदारी का तत्व गायब है। वैसे भी कंगना न तो स्वयं किसान परिवार से हैं और न ही इस आंदोलन के साथ उनका किसी तरह का कोई संबंध रहा है। हाल में एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि दिल्ली की सीमा पर हुए किसान आंदोलन के दौरान प्रदर्शन स्थल पर लाशें लटकती देखी गईं और बलात्कार हो रहे थे। उन्होंने कहा कि यदि मोदी सरकार ने कड़े कदम नहीं उठाए होते तो किसानों के विरोध प्रदर्शन से भारत में बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा हो सकती थी। इस बयान ने उन भाजपाइयों को भी चौंका दिया जो, लोकसभा चुनाव में हुई चूकों की राजनीतिक दुरूस्ती में लगे हुए हैं। इस बयान से संभावित सियासी नुकसान को भांपकर भाजपा ने तुरंत खंडन जारी किया कि कंगना का बयान पार्टी की अधिकृत राय नहीं है। उन्हें नीतिगत मामलों पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। साथ में कंगना को चेतावनी दी गई कि वो आइंदा ऐसे मुद्दों पर न बोलें। उधर विपक्ष ने इस बयान को तुरंत लपका और भाजपा पर प्रहार शुरू कर दिए।

नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि कंगना का बयान भाजपा की किसान विरोधी नीति का सबूत है। इसे किसी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि किसानों से किए वादे पूरा करने में नाकाम रहा तंत्र किसानों के प्रति दुष्प्रचार में लगा हुआ है। राहुल ने कहा कि भाजपा कंगना के बयान से असहमत है तो उन्हें पार्टी से बाहर करे। उन्होंने यह भी कहा कि तीन विवादित कृषि कानूनो के खिलाफ 378 दिन चले मैराथन संघर्ष में 700 किसानों ने बलिदान दिया। उन्हें बलात्कारी व विदेशी ताकतों का नुमाइंदा कहना भाजपा की किसान विरोधी नीति व नीयत का परिचायक है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के किसानों का अपमान है। इंडिया गठबंधन किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी दिलवा कर रहेगा। कुछ ऐसे ही बयान आम आदमी पार्टी, सपा की तरफ से भी आए। क्योंकि सबको पता है कि किसानों का मुद्दा हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तरप्रदेश के लिए कितना संवेदनशील है। इस मामले में कोई भी प्रतिकूल प्रतिक्रिया भाजपा की जमावट को जड़ से हिला सकती है। दरअसल, ऐसे आत्मघाती बयान या तो अतिआत्मविश्वास की कोख से जन्म लेते हैं या फिर विवेकहीनता का परिणाम होते हैं। इसमे यह उद्दंड भाव छिपा होता है कि जनता उनकी बंधुआ है। वो कुछ भी करें या कहें, सत्ता उन्हीं के हाथ रहनी है।

लोकसभा चुनाव के पहले भाजपा का 'अबकी बार चार सौ पार का नारा' भी इसी मुगालते का नतीजा था। तीन विधानसभा चुनावों में भाजपा की बंपर जीत और राम मंदिर में भगवान राम की भव्य प्रतिष्ठापना ने ऐसी सियासी धुंध पैदा की कि सत्ताधीशों को शायद सतह के नीचे की खदबदाहट सुनाई देना ही बंद हो गई। यह राजनीतिक बधिरता ही ऐसे बयानों को प्रेरित करती है, जो अपने घर पर ही बुलडोजर चलाने जैसी साबित होती है। लोकसभा चुनाव के समय भी यही हुआ था। चार सौ पार इसलिए चाहिए क्योंकि संविधान बदलना है, यह नरेटिव गुप्त गंगा की तरह ऐसा लहराया कि चार सौ पार तो दूर भाजपा बहुमत के आंकड़ों से भी 32 सीट दूर रह गई। इसकी शुरुआत भी किसी विपक्षी पार्टी ने नहीं बल्कि 'कंगना कल्चर' के भाजपाई सांसदों अनंत हेगड़े, ज्योति मिर्धा, लल्लू सिंह, अरूण गोविल आदि ने की थी।

कांग्रेस और विपक्ष ने इसी बड़बोलेपन को अपना अचूक हथियार बनाकर भाजपा की नीयत पर ही हमले शुरू कर दिए। डेमेज कंट्रोल के तौर पर भाजपा ने कुछ सांसदों के टिकट भी काटे, लेकिन पार्टी की मंशा पर उठी उंगलियों को वापस मोड़ देने का कोई कारगर इलाज उसके पास नहीं था। जब तक वो इन सवालों का माकूल राजनीतिक जवाब देती, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भाजपा की परेशानी यह है कि अब राहुल गांधी उसकी दुखती रग बने चारों मुद्दों पर लगातार और बेखौफ हमला किए जा रहे हैं। ऐसे में राहुल को 'पप्पू' अथवा 'अपरिपक्व राजनीतिज्ञ' साबित करने के पुराने फार्मूले काम नहीं आ रहे हैं। बीते दस सालों में यह शायद पहली बार है, जब देश तो क्या विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली भाजपा अपना एजेंडा सेट करने के बजाए विपक्षी हमलो से बचाव के लिए तलवार पर धार करने में ही उलझी है। यह बात मोदी सरकार के कोर मुद्दों पर बैकफुट पर जाने और अपने ही नेताओं को कायदे में न रख पाने से जाहिर है। कंगना के ताजा बयान से हरियाणा में भाजपा का कितना नुकसान होगा या नहीं होगा, यह तो विधानसभा चुनाव के नतीजों से पता चलेगा, लेकिन पार्टी कंगना के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई करने की स्थिति में नहीं है। यह साफ है।

समय के साथ पेशेवर बन जाए पुलिस

अब देश में आए दिन जो आंदोलन या प्रदर्शन होने लगे हैं, उनमें पिछले दिनों बढ़ोतरी नजर आई है और आने वाले दिनों में ऐसे प्रदर्शन बढ़ने वाले हैं। कोलकाता से मुंबई तक और चेन्नई से श्रीनगर तक जन प्रदर्शन बढ़ने की आशंका अनेक वजहों से हो सकती है। जहां लोगों के हित प्रभावित होते हैं, वहां विरोध प्रदर्शन की स्थिति बन जाती है। राजनीतिक प्रदर्शन हो, किसानों का प्रदर्शन हो या छात्रों, चिकित्सकों, दलितों का प्रदर्शन, जहां भी हितों का टकराव होगा, जहां भी किसी वर्ग के हित प्रभावित होंगे, वहां प्रदर्शन की स्थिति बनेगी। सचेत रहना होगा। बदलते समय और समाज में लोगों की बढ़ती आकांक्षाओं या स्वार्थ की वजह से भी ऐसे प्रदर्शन लगातार बढ़ते जाएंगे।

सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि जो प्रदर्शन होते हैं, उनका आकार-प्रकार क्या है? दूसरी बात, यह पुलिस की जिम्मेदारी है कि वह एक मुकम्मल व्यवस्था को हर हाल में बनाए रखे। यह गौर करने की बात है कि पुलिस लोगों के बीच तभी जाती है, जब आंदोलन उग्र होने की आशंका होती है। शांति भंग की स्थिति में यह पुलिस की ही जिम्मेदारी है कि वह स्थितियों को नियंत्रित करे। यह कोई व्यक्तिगत मसला नहीं है, इसे समाज व संविधान ने बाध्यकारी बना रखा है कि उपद्रव की जगह पुलिस को पहुंचना होगा, कानून-व्यवस्था को बहाल करना होगा।

बहरहाल, अगर पुलिस कम कड़ाई करे, तो भी आलोचना होती है और ज्यादा कड़ाई कर दे, तब भी आलोचक तीखे शब्दों के साथ कूद पड़ते हैं। मूकदर्शक होने और ज्यादती करने के बीच की रेखा बहुत बारीक है। पुलिस के सामने यह चुनौती शायद हमेशा रहेगी कि वह अतिवादी आरोप से बची रहे। पुलिस बनी ही इसलिए है कि हर हाल में व्यवस्था बनी रहे। उसे हमने ताकत दी है, अब उसे ऐसे काम करना चाहिए कि आरोप न लगे।

ऐसे मौके जब भी आते हैं, तो पुलिस को एसओपी (मानक संचालन प्रक्रियाओं) का इस्तेमाल करना चाहिए। पुलिस को कब क्या करना है, यह सब पहले से ही बहुत सोच-समझकर तय है। कब बल प्रयोग करना है, कितना बल प्रयोग करना है, यह सब तय है और पुलिस को हर हाल में एसओपी के अनुरूप ही काम करना चाहिए।

दूसरी बात, बल प्रयोग का सिद्धांत यह है कि पुलिस न्यूनतम मात्रा में ही बल प्रयोग करे। वास्तव में कम मात्रा में बल प्रयोग ही प्रभावी होता है। भीड़ का व्यवहार देखते हुए आचरण होना चाहिए। तीसरी बात, पुलिस को अति उत्साह से बचना चाहिए, संयम से काम लेना चाहिए। पुलिसकर्मी कई बार संयम खो देते हैं, तभी उनकी लाठी अपने अधिकारियों पर भी चल जाती है, जैसा हमने पिछले दिनों पटना में देखा है। भीड़ पर नियंत्रण से पहले पुलिस का खुद पर भी नियंत्रण होना चाहिए।

पूरे भारत में पुलिस सबसे बड़ी गलती यह करती है कि वह खुद भीड़ का हिस्सा हो जाती है। अगर बल प्रयोग करना है, तो पुलिस को भीड़ में कभी शामिल नहीं होना चाहिए। पुलिस जब भीड़ में घुलमिल जाती है, तो उसके बड़े दुष्परिणाम होते हैं। अगर वह भीड़ में घुसकर बल प्रयोग करती है, तो ज्यादा लोगों को नुकसान पहुंचाती है। पुलिस को किसी भी तरह की हड़बड़ाहट से बचना है।

मैंने देखा है, अनेक पुलिसकर्मी या जवान अपने हथियार के साथ भीड़ में घूमते रहते हैं। इससे खुद उन पर खतरा बढ़ जाता है। अराजक तत्वों या हमलावरों को भी इससे आसानी हो सकती है। बंदूकें लेकर भीड़ में घूमना अनुशासनहीनता है।

मैं जब एक जनपद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक था, तब मैंने नेताओं या अन्य लोगों की सुरक्षा में लगे जवानों को हर शुक्रवार को परेड में बुलाना शुरू कर दिया था। कुछ लोगों ने आपत्ति भी की, पर मैंने बताया कि यह आपकी सुरक्षा के लिए भी जरूरी है, पुलिस का जवान अनुशासन में रहे, हमेशा तैयार रहे। ऐसा न हो कि आपकी सुरक्षा में लगा हो और चप्पल पहनकर घूमने लगे। ऐसा जवान जो तैयार नहीं है, वह आपकी क्या सुरक्षा करेगा? नेताओं व अन्य लोगों को भी यह बात समझ में आई कि मैं ठीक कर रहा हूं। एक जवान को कड़ाई से अनुशासन में रखना ही चाहिए।

पिछले बीस साल में भीड़ नियंत्रण हेतु बहुत सारे सुरक्षा उपकरण आए हैं, आधुनिक वाहन आ गए हैं, वीडियोग्राफी भी होने लगी है। बहुत सारे उपाय हैं, जिनसे भीड़ को नियंत्रित किया जा सकता है और जनहानि भी कम हो सकती है। दिल्ली में ही अगर आप देखिए, तो पुलिस ज्यादातर वाटर केनन का ही इस्तेमाल करती है। बदलते समय के साथ पुलिस को भीड़ को नियंत्रित करने के नए तरीके खोजने होंगे। देश में आबादी बढ़ रही है और जगह-जगह भीड़ का आलम है, अगर कहीं उपद्रव की स्थिति बनी, तो पुलिस को इतना अनुशासनित और सुसज्जित होना ही चाहिए कि वह समय रहते हालात को अपने नियंत्रण में ले ले। भीड़ पर नियंत्रण के लिए रबर बुलेट भी आई थी, पर उपद्रवियों ने जान लिया कि इससे कोई खास नुकसान नहीं है। फिर भी जहां जरूरी हो, इस रबर बुलेट का सीमित प्रयोग करना चाहिए। न्यूनतम बल के इस्तेमाल से अगर बात बन जाए, तो इससे बेहतर कुछ नहीं।

तय है, जैसे-जैसे भीड़ बढ़ेगी, तनाव बढ़ेंगे, आंदोलन बढ़ेंगे, वैसे-वैसे आम लोगों के बीच भी सतर्कता बढ़ती जानी चाहिए। लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन को प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता, लोग अपनी भावनाओं के इजहार के लिए घरों से बाहर निकलेंगे और जगह-जगह एकत्रित भी होंगे, पर लोगों को स्वयं भी कानून-व्यवस्था की चिंता होनी चाहिए। कानून हाथ में लेने की वजह से अगर एक भी व्यक्ति की जान जाती है, तो इसके लिए भीड़ या आम लोग भी दोषी हैं। मुसीबत पड़ते ही लोग अपने-अपने बचाव में लग जाते हैं, सामूहिकता खत्म हो जाती है और भगदड़ मच जाती है। ऐसी स्थिति में लोगों की भी जिम्मेदारी है कि किसी भी विरोध प्रदर्शन के दौरान उनका अपने समूह पर नियंत्रण हो। समूह के नेता सभी को अनुशासन में रहने के लिए प्रेरित और बाध्य करें। अमन-चैन हर किसी के भले के लिए है।

हमें सावधान रहना होगा, बढ़ती भीड़ के साथ अफवाहों का भी खतरा बढ़ता जाएगा। हर किसी की दिमागी स्थिति ऐसी नहीं होती कि वह अफवाहों को समझ सके। अतः यहां भी समूह के नेताओं को ज्यादा सजग रहना चाहिए। भीड़ पर नियंत्रण की तरह ही अफवाह पर नियंत्रण भी जरूरी है। आज हम जिस दौर में रह रहे हैं, किसी भी सूचना पर अचानक से विश्वास नहीं करना चाहिए, हर सूचना को देखना-परखना पहले की तुलना में ज्यादा जरूरी हो गया है। पुलिस को ही नहीं, लोगों को भी चौकस रहना होगा। अपने देश में ही नहीं, विदेश में भी लोग सोशल मीडिया से प्रभावित होकर सड़कों पर उतर जा रहे हैं। दुनिया में कहीं भी सोशल मीडिया पर लम्बे समय तक रोक नहीं लग सकती, पर लोगों को सूचनाओं के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। सोशल मीडिया जैसा हथियार जागरूक लोगों के हाथों में ही कारगर होगा। पुलिस की भी जिम्मेदारी बढ़ गई है कि वह सोशल मीडिया में चल रही सूचनाओं-अफवाहों पर खासतौर पर निगाह रखे।

आज आप गौर कीजिए, पहले लंदन में दंगे नहीं होते थे, फ्रांस में दंगे नहीं होते थे, पर अब हर जगह

दंगे होने लगे हैं। कानून-व्यवस्था में गड़बड़ी वाली जो स्थिति है, वह केवल भारत में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में है। आप गौर कीजिए, पूरे विश्व में जगह-जगह आंदोलन प्रदर्शन होने लगे हैं। लोकतंत्र में यह जरूरी भी है, लोगों को इजहार का मौका मिलता है, पर आंदोलन का भी एक वाजिब तरीका होना चाहिए। हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य यही रहना चाहिए कि कानून-व्यवस्था हर हाल में बनी रहे।

पुलिस पहले की तरह काम करती रहेगी, तो उसकी परेशानियां बढ़ती जाएंगी। पुलिस सत्ताधारी पार्टी की सेवा के लिए नहीं है, यह लोगों की सेवा के लिए है। पुलिस में यह कमी है कि वह अकसर प्रजा के बजाय राजा के प्रति ज्यादा निष्ठावान हो जाती है और यहीं सबसे बड़ा खतरा पैदा होता है। शासकों के आदेश की पालना में कानून को भी कई बार ताक पर रख दिया जाता है। अतः पुलिस को समझना होगा कि वह समय के साथ पेशेवर बन जाए। स्थितियों के अनुरूप ढल जाए। उसे निष्पक्ष रहना होगा तथा अपनी विश्वसनीयता बढ़ानी होगी।

जो भी कदम व्यापक जनहित और संविधान के अनुरूप है, उसी के पक्षधर हो जाइए। ऐसा न हो कि पुलिस किसी को सबक सिखाने में लग जाए। आगे खूब उकसाने वाले मिलेंगे, पर किसी उकसावे में नहीं आना है। हर पक्ष को समझना चाहिए और न्यायपूर्ण फैसला लेना चाहिए। अंत में सभी भागीदारों - पुलिस, जनता, शासकों, आंदोलनकारियों को समझना होगा कि शांति कायम रखना उन सभी की साझा जिम्मेदारी है ।

उत्पीड़न के दानव का कैसे हो दमन?

देश में उत्सवों और त्योहारों का दौर चल रहा है, पर बार-बार कोलकाता कांड की खबरें सुर्खियों में आ-जा रही हैं। डॉक्टरों और युवाओं की नाराजगी का दौर थम नहीं रहा है। एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ अस्पताल में हुई बर्बरता का गहरा साया नौजवानों को सता रहा है। आक्रोश इस तरह फूटा है कि सर्वोच्च न्यायालय को भी खुद संज्ञान लेकर निर्देश जारी करने पड़े हैं। समाचार-पत्रों में बलात्कार, यौन उत्पीड़न की घटनाओं की प्रचुरता हो गई है। असम में 14 वर्षीय लड़की का गैंगरेप, बदलापुर (महाराष्ट्र) में अबोध बच्चियों का त्रासद प्रकरण, अन्य स्थान पर 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला से बलात्कार और स्पेनिश पर्यटक का छत्तीसगढ़ में गैंगरेप। उधर, हेमा रिपोर्ट के बाद केरल के फिल्म उद्योग में महिला कलाकारों के शोषण का मामला सुर्खियां बटोर रहा है। ये सब घटनाएं सोचने को मजबूर करती हैं कि क्या किसी भी उम्र की लड़कियां या महिलाएं सुरक्षित हैं? स्कूल, सड़क, बस, अस्पताल, यहां तक कि कई बार अपने घर में भी क्या महिलाएं सुरक्षित हैं?

क्या हमारा अमृत काल आधी आबादी, यानी महिलाओं की सुरक्षा के बिना साकार हो सकता है? भौतिक, आर्थिक व औद्योगिक विकास तो सामाजिक विकास या सुरक्षा के बिना अधूरा है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार, प्रत्येक 16 मिनट में देश में एक बलात्कार होता है और प्रत्येक घंटे महिलाओं के विरुद्ध 50 अपराध होते हैं। प्रत्येक दिन देश में 86 बलात्कार रिपोर्ट होते हैं। यह भी कहा जाता है कि सभी अपराधों में बलात्कार सबसे कम रिपोर्ट होता है और 63 प्रतिशत बलात्कार तो दर्ज ही नहीं होते। 10 प्रतिशत बलात्कार अवयस्क, यानी 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों के साथ होते हैं और 89 प्रतिशत मामलों में बलात्कारी जान-पहचान का व्यक्ति होता है। यह बिंदु भी विचारणीय है कि बलात्कार के आंकड़ों में वे प्रकरण सम्मिलित नहीं हैं, जिनमें बलात्कार का प्रयास होता है या बलात्कार के उपरांत हत्या की जाती है। मतलब, महिला विरोधी कुल अपराधों की संख्या बहुत ज्यादा है। ये केवल आंकड़े नहीं हैं। प्रत्येक आंकड़े के पीछे एक बच्ची या महिला का पूरा जीवन है और उसका परिवार है। बहुत आक्रोश जताने के कुछ ही समय बाद शोषण की शिकार महिला को लोग भूल जाते हैं। अनेक पीड़िताएं मनोवैज्ञानिक रूप से पंगु हो जाती हैं। एक ही तो जीवन है, जो हमेशा के लिए बोझ बन जाता है।

एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत महाविद्यालय में किया पौधारोपण

अवसर पर एनसीसी डॉ, प्रो मीनू गिडवानी, डॉ अरूण कुमार बोडाने, आदि उपस्थित थे

भगवान दास बैरागी । सिटी चीफ ।

शाजापुर। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस बीकेएसएन शासकीय महाविद्यालय शाजापुर में बुधवार को एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता महाविद्यालय प्राचार्य डॉ बीएस विभूति ने की। विद्यार्थियों एवं स्टॉफ सदस्यों द्वारा महाविद्यालय परिसर के बॉटनीकल गार्डन में नीम, पीपल, गुड़हल, सुरजना, आवंला, सीताफल आदि के पौधे रोपित किए गए। इस दौरान महाविद्यालय प्राचार्य डॉ विभूति ने कहा कि हमें सिर्फ पर्यावरण को संरक्षित ही नही करना है, वरन पर्यावरण के साथ समय भी

बिताना है। उन्होने कहा कि पौधारोपण कर देने मात्र से हमारा उत्तदायित्व समाप्त नही हो जाता है, बल्कि पौधों को बचाना भी हमारा उद्देश्य एवं कर्तव्य होना चाहिए। कार्यक्रम के इको क्लब प्रभारी डॉ आरसी चौहान ने पर्यावरण संरक्षण के बारे में जानकारी देते हुए प्रतिदिन पौधों को सिंचित करने की अनिवार्यता के बारे में बताया। इस अवसर पर एनसीसी के डॉ वीपी मीणा, प्रो मीनू गिडवानी, डॉ अरूण कुमार बोडाने, डॉ बीके सोलंकी, डॉ पीएस परमार, प्रो धर्मेन्द्र कुमार सोनी, प्रो प्रकाश बर्फा आदि उपस्थित थे।

मानव को देव बनाती है भागवत कथा-कथा वाचक

नित्यानंद आश्रम शाजापुर में श्रीकृष्ण रुक्मणी विवाह प्रसंग पर सात दिवसीय संगीतमय भागवत कथा आयोजित

भगवान दास बैरागी । सिटी चीफ शाजापुर, परमात्मा लक्ष्मी के स्वामी हैं और लक्ष्मी जीव मात्र की माता हैं। यह विचार नित्यानंद आश्रम में आयोजित सात दिवसीय संगीतमय भागवत कथा के दौरान बुधवार को श्रीकृष्ण रुक्मणी विवाह प्रसंग पर कथा वाचक पंडित देवकरण शर्मा ने व्यक्त किए। उन्होने कहा कि संपत्ति, शक्ति और समय का सदुपयोग करें, क्योंकि सदुपयोग करने वाला देव बनता है। उन्होने कहा कि लक्ष्मी नारायण को ही प्राप्त होती है, शिशुपाल को नहीं। जो हमेशा सांसारिक और भौतिक सुखों के पीछे भागता है वही शिशुपाल है। इस दौरान दो बालिकाओं को श्रीकृष्ण-रुक्मणी के वेश में सजाया गया और मंत्रोच्चार, मंगलाष्टक के गान के साथ विवाह संपन्न कराया गया।

पर्यावरण बचाने के लिए मां अमृता देवी के साथ बलिदान हो गए थे 71 महिला और 292 पुरुष

कार्यक्रम आयोजित कर लिया पर्यावरण बचाने का संकल्प

भगवान दास बैरागी । सिटी चीफ ।

शाजापुर, भारतीय मजदूर संघ शाजापुर द्वारा मां अमृता देवी के बलिदान दिवस पर लालघाटी शाजापुर में बुधवार को पर्यावरण संरक्षण पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया गया। अतिथियों का स्वागत पुष्पमाला से किया गया। कार्यकम के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय राज्य कर्मचारी संघ के विष्णु वर्मा रहे। वहीं अध्यक्षता संजीव ढींगरा ने की। विशेष अतिथि के रूप में राजेंद्र वर्मा, गौरव सोनी, नवीन वर्मा, रमेश राठौर, जाय शर्मा, गोपाल गुर्जर, मोहन किचोलिया, सियाराम पाटीदार, जोजनसिंह राजपूत मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों द्वारा पौधारोपण किया गया और प्रकृति वंदन कर पौधों को रक्षा सूत्र बांधा गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि वर्मा ने मां अमृता देवी के बारे में बताते हुए कहा कि राजस्थान प्रांत के जोधपुर नगर से लगभग 21 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में स्थित खेजड़ी गांव में सन् 1730

ईस्वी में जोधपुर के राजा अभयसिंह को युद्ध से थोड़ा अवकाश का समय मिला तो उन्होने महल बनवाने का निश्चय किया। महल में पत्थरों की चुनाई के लिए चूने की आवश्यकता पड़ी। चूना बनाने के लिए लकड़ी की व्यवस्था करने का आदेश राजा अभयसिंह ने अपने मंत्री गिरधारीदास भंडारी को दिया। इस पर महल से करीब 25 किलो मीटर दूर खेजडिय़ा गांव पर मंत्री की नजर पड़ी जहां खेजड़ी के पेड़ों का वन था। इस पर मंत्री एवं दरबारियों ने राजा को वहां से लकडिय़ां मंगवाने की सलाह दी तो राजा ने अपनी स्वीकृति दे दी। स्वीकृति पाकर सिपाहियों ने गांव में आकर पेड़ों को जैसे ही काटना शुरु किया वैसे ही गांव की 42 वर्षीय अमृता देवी और उनकी तीन पुत्री आशु, रत्नी और भागोबाई पति रामू जी खोड़ ने सिपाहियों को ऐसा न करने का आग्रह किया। अमृता देवी ने विनम्रता से सिपाहियों से कहा कि यह वृक्ष हमारे लिए पूजनीय हैं हम इनकी पूजा करते हैं कृपया इन्हें मत काटिए, परंतु सिपाहियों ने उनकी एक न सुनी और पेड़ काटना शुरु कर दिए। इस पर अमृता देवी अपने बेटियों के साथ पेड़ से लिपट गईं और क्षणभर में उनकी की गर्दन को धड़ से अलग कर दिया गया। यह खबर जब गांव में फैली तो 84 गांव के लोग मौके पर जमा हो गए और उन्होने एक ही निश्चय किया कि सभी पेड़ों से लिपटकर अपने प्राणों की आहुति देंगे। सबसे पहले वृद्ध पुरूषों ने आहूति दी। उसके बाद ऐसा ज्वार उठा की बड़े-बूड़े, जवान, बच्चे, स्त्री, पुरुष सब में प्राणों की आहुति देने की होड़ लग गई, यह ज्वार जब शांत हुआ तब तक 71 महिलाएं और 292 पुरुष बलिदान हो गए। इस बलिदान में 36 दंपत्ति परिवार पूरी तरह स्वाहा हो गए। इसलिए इस दिन अमृता देवी के बलिदान दिवस के रूप में मनाते हैं।

शाजापुर कलेक्टर ने कहा

उपभोक्ताओं की कसौटी पर खरा उतरने के लिए उत्पादों को गुणवत्तायुक्त बनाना होगा

भगवान दास बैरागी । सिटी चीफ ।

शाजापुर, जिले के कृषकों, उद्यमियों, स्व सहायता समूहों, उद्यानिकी उत्पादों एवं प्रसंस्कृत उत्पादों को बाजार एवं उचित मूल्य दिलाने के लिए जिला पंचायत सभा कक्ष में कलेक्टर ऋजु बाफना की अध्यक्षता में क्रेता-विक्रेता एवं निर्यातकों का सम्मेलन आयोजित किया गया। इस दौरान कलेक्टर ने जिले के उत्पादकों एवं एफपीओ के पदाधिकारियों से कहा कि आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए उत्पादों को उपभोक्ताओं की कसौटी पर खरा उतरना होगा। इसके लिए उत्पादों की गुणवत्ता मेंटेन रखना होगा। एफपीओ अपनी आय वृद्धि के लिए फसलों की उत्पादकता में एकरूपता रखें और गुणवत्ता मेंटेन करें। कलेक्टर ने उद्यानिकी, कृषि एवं आत्मा के अधिकारियों को निर्देश दिए कि एफपीओ एवं उत्पादकों को एक्सपोजर विजिट कराएं। इस दौरान राज्य नीति आयोग की सलाहकार जरीन सदाफ खान ने कहा कि राज्य सरकार उत्पादकों

को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक कदम उठाने जा रही है। उत्पादकों को उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार करना होगा। साथ ही उत्पादकों के सहयोग के लिए नाबार्ड द्वारा समाधान निकाला जा रहा है। एक एप्प भी बनाया जा रहा है जिस पर उत्पादकों को अपने उत्पाद का पंजीयन कराना होगा। इसके बाद उत्पादकों को बाजार उपलब्ध कराने के लिए राज्य शासन सहायता करेगी। सम्मेलन में लायंस इम्पेक्स नवी मुम्बई महाराष्ट्र के भारत भूषण खरबन्दा ने उद्यानिकी फसलों का खाद्य प्रसंस्करण, गुणवत्ता एवं खाद्य सुरक्षा, पैकेजिंग तकनीक, व्यापार प्रक्रिया, चुनौतियां एवं निदान, लायसेंसीकरण प्रक्रिया, आलू-प्याज, लहसून का श्रेणीकरण एवं छटाई, बाजार हेतु पैकेजिंग तकनीक, फार्मर प्रोड्यूसर संगठन पर विस्तार से जानकारी दी। इसी तरह सिद्धी विनायक, एग्री प्रोसेसिंग प्रालि पुणे के गणेश पंवार ने आलू उत्पाद की तकनीक में उच्च गुणवत्ता के प्रचलित किस्मों का बीजोत्पादन, उचित भण्डरण एवं आपूर्ति श्रृंखला तथा सर्वोत्तम श्रेणी के प्रसंस्करण एवं व्यापार के बारे में विस्तार से जानकारी दी। एक्सेस डेवलपमेंट सर्विसेस दिल्ली के चिंतन मेघवंशी ने अनुबंध खेती और एफपीओ, एसएसजी एवं सीएलएफ द्वारा साझेदारी की खेती सहित अन्य विधियों से आर्थिक विकास पर व्याख्यान दिया।

लालबर्रा सरस्वती मंच पर अतिथि शिक्षकों की बैठक आज

दोपहर 2 बजे से आहूत बैठक में बनाई जाएगी रूपरेखा

लाकेश पंचेश्वर । सिटी चीफ ।

लालबर्रा, अतिथि शिक्षक संघ लालबर्रा के वरिष्ठ सदस्य प्रवीण बहरे ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि आज 29 अगस्त को दोपहर 2 बजे से अतिथि शिक्षक संघ लालबर्रा के बैनर तले लालबर्रा नगर मुख्यालय स्थित सरस्वती मंच में विकासखण्ड स्तरीय बैठक आहूत की गयी है।श्री बहरे ने आगे बताया कि आहूत बैठक मुख्य विषय(मेन एजेंडा)बीते वर्ष 2 सितम्बर 2023 अतिथि शिक्षक महापंचायत में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा अतिथि शिक्षक महापंचायत में किये गए वादों को पुन: याद दिलाकर किये गए वादों को पूरा करवाने का है,साथ ही आहूत बैठक में अन्य विषयों पर चर्चा के साथ प्रदेश संगठन के आव्हान पर आगामी 5 सितम्बर

को होने वाले आंदोलन में अतिथि शिक्षक साथियों की सहभागिता को लेकरविचार-विमर्श किया जाएगा। आहूत बैठक में लालबर्रा विकासखण्ड के समस्त अतिथि शिक्षक साथियों से नियत समय एवं नियत स्थान में पहुंचकर बैठक में अपनी उपस्थिति दर्ज कर आहूत बैठक को सफल बनाने की अपील अतिथि शिक्षक संघ लालबर्रा के वरिष्ठ सदस्य सुदर्शन बिसेन, मुकेश कुमार सर्राटे,श्रीमती इंद्राणी सोलंकी,संजय चांदेकर,संध्या बोपचे बिसेन,संजय पंचेश्वर, दिनेश तुलसीकर,अकील अखूतर,प्रवीण बिसेन,श्रीमती ज्योति बाघमारे,नरेंद्र चौहान सहित समस्त पदाधिकारीयों एवं सदस्यों ने की है।

जिलाधिकारी की अध्यक्षता में डीएलआरसी एवं डीसीसी की बैठक सम्पन्न

बैंक शासकीय योजनाओं में ऋण देने में दिलचस्पी दिखाएं - जिलाधिकारी मनीष बंसल

गौरव सिंघल । सिटी चीफ ।

सहारनपुर, जिलाधिकारी सहारनपुर मनीष बंसल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय समीक्षा समिति एवं जिला सलाहकार समिति की बैठक आहूत की गई। बैठक में डीएम मनीष बंसल ने जनपद के ऋण जमा अनुपात (सीडी रेशियो) को बढ़ाने के लिए बैंक समन्वयकों को निर्देशित किया। उन्होंने निर्देशित किया कि बैंक शासकीय योजनाओं में ऋण देने में दिलचस्पी दिखाएं। उन्होंने बैठक में आने से पूर्व सभी अधिकारियों को अद्यचन सूची के साथ उपस्थित होने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी बैंक प्रतिनिधियों को निर्देश दिए कि बैठक में आने से पूर्व सभी लम्बित प्रकरणों को निस्तारित करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सभी बैंक सकारात्मकता से कार्य कर परिणाम देने वाले बनें।

जिलाधिकारी मनीष बंसल ने कहा कि बैंकों द्वारा दिये गये छोटे-छोटे ऋण से ही आमजन की आर्थिक

समृद्धि आएगी जिससे हम अपने आर्थिक उन्नति के लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। केंद्र एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ शासन की मंशा के अनुरूप लाभार्थियों को दिलाना सुनिश्चित करें। बैंक लक्ष्य निर्धारित कर कार्यों को करना सुनिश्चित करे। उन्होने एलडीएम को निर्देश दिए कि प्रत्येक 03 माह के अंतराल पर एक ऋण मेला आयोजित किया जाए जिसमें बैंक, संबंधित विभाग तथा आवेदक की उपस्थिति हो और प्रकरण को त्वरित रूप से निस्तारित किया जाए। डीएम मनीष बंसल ने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की प्रगति के लिए ग्राम प्रधान सचिव एवं पंचायत सहायक तथा बीसी सखी के माध्यम से आमजन को जागरूक करने के निर्देश दिए। उन्होंने एलडीएम को निर्देश देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में लोगों को दिए गये क्लेम का प्रचार-प्रसार अखबारों सहित अन्य माध्यमों से किया जाए ताकि आमजन इससे मिले फायदों के बारे में जान सके।

जिलाधिकारी मनीष बंसल ने निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना संबंधी बैनर प्रत्येक बैंक शाखा में लगाया जाए ताकि बैंक में आने वाले व्यक्तियों को इससे मिलने वाले लाभों के बारे में जानकारी मिल सके। उन्होंने बैंक प्रतिनिधियों से योजनाओं के लिए दिये गये आवेदनों में कम आवेदन स्वीकृति पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि लोन संबंधी पत्रावलियों को अनावश्यक रूप से लम्बित न रखा जाए। लोन संबंधी पत्रावली या तो स्वीकृत की जाए या सुस्पष्ट कारणों के साथ अस्वीकृत की जाए। डीएम मनीष बंसल ने पीएम स्वनिधि योजना के तहत निकायवार लम्बित वैण्डर्स एवं फैमिली प्रोफाइलिंग को शत-प्रतिशत करने के निर्देश दिए। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूहों के खाते शहरों में भी खोले जाएं। अक्रियाशील वैण्डर्स को वैध क्यू आर कोड के माध्यम से क्रियाशील किया जाए। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी सुमित राजेश महाजन, आरबीआई प्रतिनिधि मार्कण्डेय चतुर्वेदी, एलडीएम प्रवीण जमुआर सहित सभी बैंकों के प्रतिनिधि एवं सबंधित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे।

सहारनपुर में बढ़ रही ट्रैफिक जाम एवं अतिक्रमण की समस्याओं को दूर करने के संबंध में मण्डलायुक्त ने अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

गौरव सिंघल । सिटी चीफ ।

सहारनपुर, मंडलायुक्त डॉक्टर हृषिकेश भास्कर यशोद की अध्यक्षता में सहारनपुर शहर में बढ़ रही ट्रैफिक जाम एवं अतिक्रमण की समस्याओं को दूर करने के संबंध में सर्किट हाउस सभागार में बैठक सम्पन्न हुयी। बैठक में महापौर नगर निगम डॉ0 अजय सिंह, विधायक सहारनपुर राजीव गुम्बर, जिलाधिकारी मनीष बंसल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर रोहित सिंह सजवान, नगर आयुक्त संजय चौहान, उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण संतोष कुमार राय, सम्भागीय परिवहन अधिकारी सहारनपुर देवमणि भारतीय, नगर मजिस्ट्रेट सहारनपुर गजेन्द्र कुमार, एस0पी0 ट्रैफिक सिद्धार्थ वर्मा, उप जिलाधिकारी सदर युवराज सिंह, विधायक रामपुर मनिहारान के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। बैठक में मण्डलायुक्त हृषिकेश भास्कर यशोद ने नगर आयुक्त को निर्देश दिए कि स्कूल बसों के संचालन में सुगमता रहे ताकि बच्चों को ज्यादा देर ट्रैफिक में न रहना पडे इस हेतु भी नगर निगम द्वारा कार्ययोजना तैयार की जाये। उन्होंने कहा कि श्रीराम चौक, भगत सिंह चौक, शहीद चौक, चौक फब्बारा, घण्टाघर चौक एवं दिल्ली रोड पर नगर निगम द्वारा विशेष ध्यान केन्द्रित किया जाये। डॉ0 हृषिकेश भास्कर यशोद ने मुख्य मार्गो से ट्रैफिक का बोझ हटाने के लिए ट्रैफिक पुलिस द्वारा मार्ग परिवर्तन कार्य योजना तैयार किए जाने के निर्देश दिए। इस कार्य में जिला प्रशासन, विकास प्राधिकरण, पुलिस प्रशासन, नगर निगम, आर0टी0ओ0 विभागों को अपनी अहम भूमिका निभाएं। नगर आयुक्त द्वारा अवगत कराया गया कि सडकों को चिन्हित करते हुए चरणबद्व तरीके से ट्रैफिक जाम के सुधार हेतु कार्यवाही की जायेगी। प्रथम चरण में सडकों से अस्थायी अतिक्रमण को हटवाने की कार्यवाही की जायेगी। होकर्स, वैण्डर, पटरी दुकानदार आदि के लिए सुनियोजित पद्धति से स्थान चिन्हित किये जायेगें। इसी प्रकार ई-रिक्शा ऑटों रिक्शा खडे होने हेतु स्थान चिन्हित किये जायेगें व उनकी संख्या निर्धारित की जायेगी कि किस स्थान पर कितने ई-रिक्शा व ऑटो रिक्शा खडे होंगें।

निवेश मित्र पोर्टल पर निर्धारित समय सीमा के उपरान्त लम्बित न रहे प्रकरण - मंडलायुक्त डा. हृषिकेश भास्कर यशोद

मंडलायुक्त की अध्यक्षता में हुई उद्योग बंधु की मंडलीय बैठक

गौरव सिंघल । सिटी चीफ ।

सहारनुपर, मंडलायुक्त सहारनपुर डॉक्टर हृषिकेश भास्कर यशोद की अध्यक्षता एवं जिलाधिकारी मनीष बंसल की उपस्थिति में सर्किट हाउस सभागार में मण्डलीय उद्योग बन्धु की बैठक आहूत की गयी। बैठक में मंडलायुक्त डॉक्टर हृषिकेश भास्कर यशोद द्वारा तीनों जनपदों की जिला उद्योग बन्धु में विचाराधीन प्रकरणों की विस्तार से समीक्षा की गयी।

मंडलायुक्त डॉक्टर हृषिकेश भास्कर यशोद द्वारा यूपीसीडा को नाले निर्माण हेतु खुदाई शुरू किये जाने के निर्देश दिये गये। आर0एम0, यूपीसीडा, मेरठ द्वारा अवगत कराया गया कि औद्योगिक क्षेत्र, पिलखनी में पानी की निकासी हेतु नाला निर्माण के लिए अधिग्रहित किये जाने वाली भूमि के 04 कातकारों में से 02 की रिपोर्ट यूपीसीडा को उपलब्ध है, एक प्रकरण में वारिस निर्धारित किया जाना है तथा एक प्रकरण में कार्यवाही की जा रही है। मंडलायुक्त ने उपायुक्त उद्योग तथा बीपीसीएल को औद्योगिक क्षेत्र पिलखनी की इकाइयों से बीपीसीएल के साथ एग्रीमेन्ट कराने हेतु एक कैम्प लगाने के निर्देश दिये। औद्योगिक क्षेत्र, पिलखनी में पुलिस चौकी की स्थापना हेतु स्टीमेट में कुछ आपत्तियां लगायी गयी थी, जिसे दूर कर मुख्यालय भेज दिया गया है तथा 04 दुकानों हेतु भूखण्ड का सृजन करते हुए मुख्यालय की स्वीकृति उपरान्त आवंटन/ई-नीलामी की कार्यवाही की जायेगी।

विनियर व प्लाईवुड के लाईसेंस लेने हेतु आवेदन करते समय लगने वाले प्रपत्रों की जानकारी उद्यमियों को देने के संबंध में औद्योगिक संगठनों एवं उद्यमियों के साथ

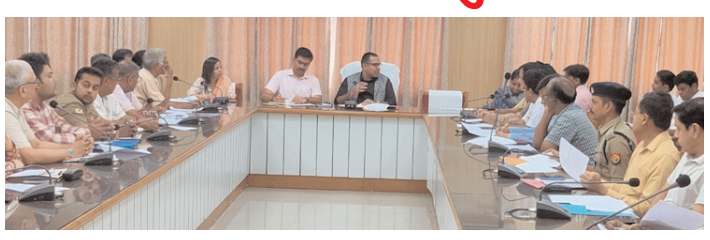

एक वर्कशॉप आयोजित किये जाने के निर्देश डीएफओ व उद्योग विभाग को दिये गये। मण्डलायुक्त हृषिकेश भास्कर यशोद ने कुम्हारहेडा, देहरादून रोड से आगे के नाले के अतिक्रमण को हटाये जाने के निर्देश अपर नगर आयुक्त को दिये। उपायुक्त उद्योग द्वारा अवगत कराया गया कि मुजफ्फरनगर में भोपा रोड पर फायर स्टेशन की स्थापना हेतु भूमि का चिन्हिकरण कर स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है तथा खसरा खतौनी में भूमि को अग्निशमन के नाम दर्ज कराने की कार्यवाही की जा रही है। मंडलायुक्त द्वारा निर्देश दिये गये कि मण्डल के जनपदों के निवेश मित्र पोर्टल पर निर्धारित समय सीमा के उपरान्त लम्बित प्रकरणों का निस्तारण किया जाये। बैठक में संयुक्त आयुक्त उद्योग श्रीमती अन्जू रानी, अपर नगर आयुक्त राजेश यादव, एसडीएम-सदर युवराज सिंह, आरएम-यूपीसीडा राजेश झा, डीएफओ श्वेता सैन, आईआईए से अनूप खन्ना, मण्डलीय अध्यक्ष-लघु उद्योग भारती अनुपम गुप्ता, अध्यक्ष-सीआईएस रविन्द्र मिगलानी तथा अन्य विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे।

अनुपपुर कलेक्टर ने ग्राम परसवार, मौहरी, धिरौल, पटनाकला व सकरा में चल रहे ई-केवायसी व नक्शा तरमीम कार्य का लिया जायजा

आधार ई-केवाईसी भू-अभिलेख पोर्टल से करने के दिए निर्देश

यशपाल सिंह जाट । सिटी चीफ ।

अनूपपुर, कलेक्टर श्री हर्षल पंचोली द्वारा राजस्व कार्यो की मॉनिटरिंग के तहत किसानों की भूमि के खसरा को समग्र तथा आधार से ई-केवायसी कार्य तथा नक्शा तरमीम कार्य का जनपद पंचायत जैतहरी के ग्राम पंचायत परसवार, मौहरी, धिरौल, पटनाकला, सकरा पहुंचकर अवलोकन किया तथा मौके पर मौजूद ग्रामीणों तथा मैदानी अमले से अभियान के तहत किया जा रहे कार्यों के संबंध मे जानकारी ली। गौरतलब है कि नागरिकों को बेहतर राजस्व सेवाएं प्रदान करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा नामांतरण, बंटवारा, नक्शा तरमीम, सीमांकन, ई-केवाईसी सहित विभिन्न राजस्व सेवाओं के लंबित प्रकरणों के शत-प्रतिशत निराकरण करने के लक्ष्य के अनुरूप कार्य किए जा रहे हैं। इस दौरान नायब तहसीलदार श्री मंगलादास चक्रवर्ती व संबंधित जन उपस्थित थे। भ्रमण के दौरान कलेक्टर ने

ग्राम धिरौल में बड़ी संख्या में ई-केवाईसी के प्रकरण लंबित रहने पर ग्राम रोजगार सहायक को कार्यों में गति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि समय-सीमा में लंबित प्रकरणों का निराकरण नही होने पर कार्यवाही की जाएगी। ग्राम पटनाकला में ई-केवायसी तथा नक्शा तरमीम के कार्य में पटवारी द्वारा रुचि नही लिए जाने पर तथा कार्यों के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी नही देने पर नाराजगी व्यक्त की गई। ग्रामवासियों ने अवगत कराया कि लगभग 2 माह से पटवारी ग्राम में भ्रमण करने नही आए हैं। जिस पर कलेक्टर ने एसडीएम अनूपपुर को संबंधित पटवारी को निलंबित किए जाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि सभी पंचायतें भू-अभिलेख पोर्टल पर पब्लिक यूजर आईडी बनाकर आधार ई-केवाईसी का कार्य करें। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि ऐसे व्यक्ति जिनका आधार एवं मोबाइल नम्बर लिंक नही है उनका आधार ईकेवाईसी समग्र पोर्टल के माध्यम से किया जाए ।

कटनी जीआरपी थाना प्रभारी पर मारपीट का आरोप

वायरल वीडियो के बाद पुलिस अधीक्षक ने की कार्रवाई

सुनील यादव । सिटी चीफ ।

कटनी, कटनी के रंगनाथ नगर थाना क्षेत्र के हिस्ट्री सीटर एवं 19 अपराधों को घटित करने वाले शातिर बदमाश दीपक वंशकार के परिजनों के साथ पूछताछ के दौरान हुई मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद रेल पुलिस अधीक्षक ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल ही कटनी जीआरपी थाना प्रभारी को पृथक कर दिया है। इस मामले की जांच उप पुलिस अधीक्षक रेल को सौंपी जा चुकी है। सोशल मीडिया में जीआरपी थाना प्रभारी के द्वारा मारपीट करने का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद मामले को गंभीरता से लेते हुए रेल पुलिस अधीक्षक ने अपने ट्वीट में उल्लेख किया है कि प्रकरण के

संज्ञान में आने के उपरांत उक्त तथ्य सामने आए हैं। ट्विटर पर दर्शित छायाचित्र माह अक्टूबर 2023 का होना पाया गया है। उक्त छायाचित्र में दर्शित व्यक्ति शातिर अपराधी दीपक वंशकार के परिजन हैं। दीपक वंशकार के विरुद्ध जीआरपी थाना कटनी में 19 अपराध दर्ज हैं। दीपक वंशकार वर्ष 2017 से निगरानी सुदा बदमाश है। पिछले वर्ष दीपक वंशकार के चोरी के अपराध में फरार होने के आधार पर इस पर 10000 का इनाम घोषित किया गया था। माह अप्रैल 2024 में इसे कटनी से जिला बदर करने के आदेश दिए गए हैं, एवं इसकी गैंग हिस्ट्री शीट खोली गई है। ट्विटर के आधार पर तथ्य सामने आने पर थाना प्रभारी जीआरपी कटनी को पृथक करते हुए मामले की जांच उप पुलिस अधीक्षक रेल को सौंप दी गई है। वही कटनी जिले के एसपी और एडिशन एसपी ने भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहे वीडियो के बारे में कहा की वायरल वीडियो में जिनके साथ मारपीट हुई है वह रंगनाथ नगर थाना क्षेत्र के निवासी है और इस मामले में जो मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में विरल हुआ है यह वीडियो जीआरपी थाना का है और इस मामले की अभी तक कोई शिकायत उनके पास नही आई है और वीडियो आते ही इस मामले के संबध में जबलपुर जीआरपी एसपी से अवगत करा दिया गया है।

अनुपपुर, रामनगर थाना द्वारा दो जुआ फड से कुल 3650 रूपये जप्त

04 जुआडियो के विरूद्ध 13 जुआ एक्ट के तहत की गई कार्यवाही

यशपाल सिंह जाट । सिटी चीफ ।अनुपपुर, थाना रामनगर द्वारा दो जुआ फड से कुल 3650 रूपये जप्त कर 04 जुआडियो के विरूद्ध की गई कार्यवाहीअनूपपुर। थाना रामनगर के द्वारा दिनांक 27.08.2024 को मुखबिर की सूचना पर खम्हाई तालाब के पास आम पेड के नीचे सेमरा में आरोपीगण 01- गौरव उपाध्याय पिता बिहारीलाल उपाध्याय उम्र 26 वर्ष निवासी वार्ड क्र0 10 ग्राम सेमरा, 02- कोट्टू उर्फ नन्दलाल केवट पिता गोविन्द केवट उम्र 45 वर्ष निवासी वार्ड क्र0 04 सेमरा थाना रामनगर के द्वारा ताश के पत्तो में कट पत्ती के द्वारा रूपये पैसो का दाव लगाकर हारजीत की बाजी से जुआ खेलते पकडे गये, उनके फड एवं पास से नगदी 1280 रूपये एवं 52 तास का पत्ता जप्त किया गया व आरोपीगणो के विरूद्ध थाना रामनगर में अपराध क्र0 289/24 धारा 13 जुआ एक्ट

की कार्यवाही की गई ।इसी प्रकार दिनांक 27.08.2024 को मध्य रात्रि मुखबिर की सूचना पर ग्राम कुहका तिराहा खोड़री नम्बर 02 में आरोपीगण 01- पप्पू चौधरी पिता स्व. लहरू चौधरी, उम्र 39 वर्ष निवासी वार्ड क्रं0 08 बदरा खेपीटोला थाना भालूमाड़ा, 02- छेदू लाल चौधरी पिता स्व. द्दी चौधरी उम्र 65 वर्ष निवासी वार्ड क्रं0 14 बदरा थाना भालूमाड़ा के द्वारा ताश के पत्तो में कट पत्ती के द्वारा रूपये पैसो का दाव लगाकर हारजीत की बाजी से जुआ खेलते पकडे जाने पर उनके फड एवं पास से नगदी 2350 रूपये एवं 52 तास का जप्त किया गया व आरोपीगणो के विरूद्ध थाना रामनगर में अपराध क्र0 290/24 धारा 13 जुआ एक्ट की कार्यवाही की गई। इस प्रकार थाना रामनगर के द्वारा सम्पूर्ण कार्यवाही से 52 ताश के पत्तो से रूपये पैसो से जुआ खेलते हुये 04 आरोपीगणो के कब्जे से कुल 3650 रूपये व 52 तास के पत्ते जप्त कर आरोपीगणो के विरूद्ध धारा 13 जुआ एक्ट की कार्यवाही की गई। उक्त कार्यवाही थाना प्रभारी रामनगर निरीक्षक अमर वर्मा के नेतृत्व में प्रआर0 72 श्रीश्याम शुक्ला, प्रआर0 84 सनत द्विवेदी, प्रआर0 11 हरीश डेहरिया, आर0 389 मनोज उपाध्याय, आर0 547 अनुराग भार्गव, आर0 529 अनुराग सिहं, आर0 309 राहुल प्रजापति, चालक आर0 262 रिन्कू गोले का सराहनीय योगदान है।

अनुपपुर आबकारी अमले द्वारा 7 स्थानों पर की गई तलाशी की कार्यवाही

3 प्रकरण किए गए दर्ज

यशपाल सिंह जाट । सिटी चीफ अनूपपुर, जिला आबकारी अधिकारी सुश्री सावित्री भगत ने बताया है कि सूचना के आधार पर वृत्त अनूपपुर के जैतहरी थाना अंतर्गत वेंकटनगर, कल्याणपुर एवं सिंघौरा में तलाशी की कार्यवाही की गई। कुल 7 स्थानों पर दबिश दी गई। 4 स्थानों पर कुछ भी अवैध पदार्थ बरामद नही हुए। 3 स्थानों से 24 पाव विदेशी मदिरा एवं 6 लीटर हाथ भट्ठी मदिरा बरामद कर 3 प्रकरण दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया है कि अवैध मदिरा के विरूद्ध कार्यवाही विभागीय अमले द्वारा सतत् रूप से कर प्रकरण कायम किए जाएंगे।

मंडल राजनगर में भाजपा के सदस्यता अभियान पर कार्यशाला का आयोजन

लघु उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल की उपस्थिति में सम्पन्न

यशपाल सिंह जाट । सिटी चीफ ।

राजनगर, भारतीय जनता पार्टी मंडल राजनगर द्वारा संगठन महापर्व के तहत भाजपा की सदस्यता विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन मधुबन क्लब राजनगर में किया गया जहां पर बतौर मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता के रूप में मध्य प्रदेश शासन के लघु एवं कुटीर उद्योगों मंत्री दिलीप जायसवाल उपस्थित रहे जहां पर विशिष्ट अतिथि के रूप में नगर परिषद बनगांव के अध्यक्ष यशवंत कुमार सिंह नगर परिषद डूमर कछार के अध्यक्ष डॉक्टर सुनील कुमार चौरसिया डोला के उपाध्यक्ष रविशंकर तिवारी सहित भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित थे तो कार्यक्रम की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष राजेश कलशा ने की जहां पर सर्वप्रथम श्यामा प्रसाद मुखर्जी दीनदयाल उपाध्याय भारत माता की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यशाला की शुरुआत की

गईजहां भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश शासन के लघु एवं कुटीर उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं पर आधारित पार्टी है जहां संविधान के अनुसार पार्टी चलती है जिसके तहत एक सितंबर से से भाजपा का सदस्यता महा अभियान चलाया जाएगा जिसमे सबसे पहले सदस्य देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे हमारा यह अभियान देश से लेकर भूतों तक चलेगा जहां हमारे सभी कार्यकर्ता सक्रिय होकर सदस्यता करेंगे भाजपा सर्वव्यापी पार्टी है जो समाज के सभी वर्गों का कल्याण करने के उद्देश्य पर काम करती हैरिसोर्स पर भाजपा के वरिष्ठ नेता आधाराम वैश्य गजेंद्र सिंह सिकरवार प्रेमचंद यादव बृजमोहन सिंह गहरवार अखिलेश द्विवेदी राजेंद्र त्रिपाठी अमृत लाल केवट सुरेश गौतम के एन शर्मा श्याम सुंदर गौतम मदन त्रिपाठी सहित भाजपा मंडल राजनगर के कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारी उपस्थित थे।

भगवान राम का नाम समस्त विकारों का नाश करने वाला है पंडित श्याम जी मनावत

काटाफोड़ सभी को गुरु को फूल अर्पित करने का अधिकार है लेकिन फल तो सतगुरु ही देते हैं संसार के समस्त ज्ञान एकीकृत करने पर भगवान शंकर की मूर्ति बनती है इस तरह संसार के सारे वैराग्य को एकीकृत करने पर हनुमान जी की मूर्ति बनती है एवं संसार के समस्त सेवा को एकीकृत करने पर भगवान लक्ष्मण जी की मूर्ति बनती है, भगवान प्रभु श्री राम सर्वत्र विराजमान है उक्त कथन नगर कांटाफोड़ में सिंगी मांगलिक भवन में चल रही राम कथा के चौथे दिवस भागवत मर्मज्ञ पंडित श्याम जी मानवत में कहे उन्होंने कहा भगवान राम का नाम समस्त विकारों को नाश करने वाला है तुझ में मुझ में हम सब में राम विराजमान है कथा के चौथे दिन भगवान श्री राम का राम विवाह का आयोजन किया गया ढोल धमाके के साथ राम जानकी रूप का चित्रण किया गया श्रद्धालुओं द्वारा पुष्प वर्षा

कर हर्षोल्लास के साथ राम जानकी विवाह का आनंद नृत्य कर लिया गया

जेतपुरा गाँव मे धूम धाम से मनाया कृष्ण जन्मोत्सव

शम्भूपुरा। ग्राम जेतपुरा के श्री बाँके बिहारी भगवान मंदिर पर इस वर्ष कृष्ण जन्मोत्सव बड़ी धूम धाम से मनाया गया। जानकारी अनुसार समस्त ग्रामीणों द्वारा 51 किलो केले, पंचामृत ओर केक काट कर पंजीरी का भोग लगाते हुए नई पोषाक भी भगवान बाँके बिहारी को धारण करवाई गई। ग्रामीणों द्वारा मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया गया। ओर दही की मटकी फोड़ प्रतियोगिता भी रखी ओर ग्रामीणों द्वारा मंदिर परिसर में चार आशापाल के पौधे, 11 गमले लगाए

गये साथ हि ओसरा पुजारी जितेंद्र वैष्णव, जमनेश वैष्णव द्वारा भगवान बाँके बिहारी जी का विशेष श्रृंगार दर्शन आरती की गई, ग्रामीण कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर काफी उत्सुक नजर आये।

निजी बसों का चक्का जाम 25 हजार यात्री हुए प्रभावित

शम्भूपुरा ।बस ऑपरेटर्स राजस्थान और बस मालिक की ओर से आज निजी बसों का चक्का जाम करते हुए प्रदेश स्तरीय हड़ताल की गई। जिसमें प्रदेश में करीब 30 हजार और जिले में 450 बसों का संचालन प्रभावित हुआ है। आज हुई निजी बसों की हड़ताल के कारण रोडवेज और ट्रेनों में भारी भीड़ देखी गई वहीं नियमित रूप से जाने वाले यात्री परेशान दिखे। खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों के रूटों पर लोगो को भारी परेशानियां हुई और कई लोग निजी वाहनों से यात्रा करने पर मजबूर हुए।

24 सूत्रीय मांगों को लेकर दिया ज्ञापन बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष सत्यनारायण साहू एवं इरशाद शेख ने बताया कि बस ऑपरेटर्स की ओर से परिवहन विभाग को कई बार मांगों से अवगत कराया है लेकिन समस्याओं का समाधान नहीं होने के कारण मजबूर होकर चक्का जाम हड़ताल का फैसला करना पड़ा। बस ऑपरेटर्स की ओर से सरकार को बार-बार 24 सूत्रीय मांगों को लेकर ध्यान आकर्षण कराया जिसमें ऑनलाईन अस्थाई परमिट के साथ-साथ ऑफलाइन परमिट चालू रखने, बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में 2 माह का टेक्स माफ करने की मांग रखी थी। उनके अनुसार निजी बसों का किराया 2014 में तय किया गया था। वहीं कई बार डीजल, बीमा, टोल और बसों के साथ-साथ पार्ट्स की कीमत बढ़ने

के बावजूद दूसरे राज्यों की अपेक्षा राजस्थान में किराया कम है।

यह रही प्रमुख मांगें बस ऑपरेटर्स ने अपनी प्रमुख मांगों को लेकर जिलाध्यक्ष इरशाद शेख के नेतृत्व में जिला कलक्टर को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने ज्ञापन में बताया कि दूसरे राज्यों के समान प्रति यात्री, प्रति किलोमीटर 1 रूपये 40 पैसे किराया तय किया जाये। चुनाव में निजी बसों का किराया 2250 रूपये से बढ़ाकर 4 हजार 500 रूपये और डीजल किया जाये। राजस्थान परमिट पर ट्यूरिस्ट पर चलने वाली बसों को यूपी, बिहार, मध्यप्रदेश की तर्ज पर 200 रूपये प्रति सीट प्रतिमाह किया जाये। लोक परिवहन सेवा, ग्रामीण सेवा, सिटी परमिट बसों की टीपी की संख्या बढ़ाई जाये। एनसीआर क्षेत्र में सीएनजी या बीएस 6 इंजन लगाने पर एनसीआर क्षेत्र में संचालन की परमिशन 10 साल तक बढ़ाई जाये। वाहन बदलने पर सिटिंग कैपिसिटी की शर्त को 5 से बढ़ाकर 20 प्रतिशत किया जाये। राजस्थान परमिट से राष्ट्रीयगत मार्ग पर संचालित नहीं करने की शर्त को हटाया जाये और 2 संभागों को जोड़कर परमिट जारी करने जैसी कई मांगें रखी है। इस संबंध में एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि रोडवेज के पास 2600 बसें होने के बावजूद 8 हजार परमिट लिये हुए है और कई राष्ट्रीयकृत मार्गों पर आम नागरिक को यातायात का साधन उपलब्ध नहीं है। जिस मार्ग पर रोडवेज का परमिट होने के बावजूद बसें संचालित नहीं है उसका परमिट निजी बसों को देने की भी मांग है।

पाम एवं सोयाबीन तेल आयात पर लगे पूर्णतः प्रतिबंध

सोयाबीन के गिरते दाम को लेकर कृषि मंत्री के नाम ज्ञापन दिया

बदनावर । भारतीय किसान संघ शाखा बदनावर द्वारा पाम तेल एवं सोयाबीन तेल के आयात को पूर्णत प्रतिबंधित करने को लेकर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम से तहसीलदार सुरेश नागर को ज्ञापन सोपा गया। ज्ञापन में बताया कि सोयाबीन फसल के भाव पिछले 10 वर्षों के पूर्व भाव पर 4000 पर प्रति क्विंटल पहुंच चुके है। पिछले 10 वर्षों में दौजात, कीटनाशक वाई, मजदूरी, ट्रैक्टर भाड़ सभी डबल हो चुके हैं। इस हिसाब से सोयाबीन का बाच किसानों को 28000 प्रति 1 क्विंटल मिलना चाहिए। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आप खुद एक किसान है आप बताएं 10 वर्षों के पूर्व के रेट में कौन सी बस्तु मिल रही है। सरकार ने ट्रैक्टर, कृषि यंत्र, कीटनाशक दवाई, खेती में उपयोग की जाने वाली यशीन रात्री सामान पर जीएसटी लगा रखा है। श्री आपको फसल 10 वर्ष के पूर्व के भाव में चाहिए सरकार से निवेदन है कि पाम तेल एवं सोयाबीन तेल आयात को । बारात में पूर्णत: बंद कर देना चाहिए। सोयाबीन डौगीसी का सादा से ज्यादा निर्यात किया जाए। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सेनाबीन का समर्थन मूल्य 4892 रुपए प्रति क्विंटल घोषित किया है है और सोयाबीन 3800 **प्रति क्विंटल विक रही है। इस मान से किसान को** प्रति क्विंटल 1000 के नुकसानी हो रही है। सरकार जिस फसल को सरकारी खरीद नहीं कर सकती उस फसल का समर्थन मूल्य तय करने का अधिकार आपको है। तो सोयाबीन की खरीद समर्थन मूल्य पर की जाए। साथ ही बदनावार क्षेत्र में चौडारोज की संख्या में बहुत वृद्धि हो चुकी है। फसलों में काफी नुकसान करता है। 4000 प्रति क्विटल भाव से फसल बेचने में किसान को घाटा ही घाटा होता है। अत: मध्य प्रदेश सरकार से अनुरोध है कि सोयाबीन की उपज शासकीय खरीदी पर 78000 प्रति क्विंटल में खरीदी की जाए। ज्ञापन देने के दौरान अध्यक्ष कालू सिंह राठौर, मंत्री रंजीत, जिला प्रचारक मनोहर कागदर, लाखन सिंह, कुलदीप, बिजय सिंह, श्रीराग, भरतलाल, शंभूसिंह, दिलीप सिंह, दरवार सिंह, मदन सिंह, पंकज पवार, अरुण सिंह, विशाल सिंह, अमृतलाल तारोदिया, काशीराम चौधरी, महेंद्र जायसवाल, राजेंद्रसिंह, मदन सिंह, बजेसिंह, चतर्रासिंह डोडिया, अंतसिंह, समंदरसिंह शिवराजसिंह सहित कई किसान मौजूद थे

स्मार्ट मीटर के विरोध में जिला पंचायत सदस्य तरूण बाहेती के नेतृत्व में जनता ने किया आंदोलन

बिजली कंपनी की नितियों के खिलाफ जनता ने निकाली भड़ास, थाली कटोरी बजाए, मीटर फोड़े और बिल की जलाई होली

नीमच। स्मार्ट मीटर के विरोध में जिला पंचायत सदस्य तरूण बाहेती के नेतृत्व में बुधवार को जनता ने आंदोलन किया। बिजली कंपनी की नीतियों के खिलाफ भारतमाता चौराहा (फोरजीरो) जनता ने प्रदर्शन किया और भड़ास निकाली। इस दौरान थाली कटोरी बजाए गए और विद्युत मीटर फोड़े और बिजली बिल की होली जलाई गई।

जब से शहर में लोगों के घरों पर स्मार्ट मीटर लगे हैं, तब से बिजली के बिल दोगुना आ रहे हैं। इसकी शिकायते लगातार बिजली कंपनी तक भी पहुंच रही है, पर शिकायतों का निराकरण करने के बजाए बिजली कंपनी के अधिकारी उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर की खुबिया बता रहे हैं। शिकायते जब जिला पंचायत सदस्य तरूण बाहेती के समक्ष पहुंची, तो तब से श्री बाहेती ने स्मार्ट मीटर के खिलाफ जनता की आवाज उठाना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में स्मार्ट मीटर के खिलाफ जनता की आवाज बुलंद करने जिला पंचायत सदस्य तरूण बाहेती के नेतृत्व में जन आंदोलन बुधवार दोपहर भारत माता चौराहा फोरजीरो पर किया। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए श्री बाहेती ने कहा कि यह आम उपभोक्ताओं की लड़ाई है जो तिरंगे झंडे के नीचे आम जनता के लिए लड़ी जा रही है। श्री बाहेती ने कहा कि बिजली कम्पनी ईस्ट इण्डिया कम्पनी जैसा व्यवहार लोगों के साथ कर रही है । बिजली कम्पनी को स्मार्ट मीटर लगाने की इतनी जल्दी थी कि पुराने मीटर हटाने और नये स्मार्ट मीटर लगाने पर उपभोक्ता की अनुमति लेना भी उचित नहीं समझा जबकि नियम है कि किसी भी घर में नये स्मार्ट मीटर लगने से पहले उपभोक्ता के सहमति हस्ताक्षर आवश्यक है। साथ ही बिजली कंपनी स्मार्ट मीटर लगाने के बाद भी कई घरों में एवरेज बिल दे रही है जो कि पूर्णतया गलत है । बाहेती ने बिजली कंपनी पर आरोप लगाते हुए कहा कि अगर बिजली कंपनी के अधिकारी को लगता है कि किसी घर का बिजली बिल कम आ रहा है तो अधिकारी उस घर में बिजली से चल रही सामग्री की गणना कर लोड चेक करते हैं और उसे उसी लोड के हिसाब से प्रति माह का बिल जनरेट कर देते हैं, इसमें उपभोक्ता को सीधा-सीधा नुकसान है कि वह किसी सामग्री का उपयोग नहीं करें तो भी उसका बिल उसे देना पड़ रहा है। जबकि नियमानुसार जितना मीटर चले उतना ही बिल होना चाहिए । जिला पंचायत सदस्य बाहेती ने कहा कि स्मार्ट मीटर से मजदूर वर्ग ज्यादा परेशान है, अगर कोई पूरे महीने भर की कमाई सिर्फ बिजली बिल भरने में ही लगा दें तो वह अपना घर कैसे चलाएगा और अपना परिवार कैसे पालेगा । बिजली कंपनी के अधिकारी शिकायत करने पर स्मार्ट मीटर की खूबियों का ऐसा महिमामंडन किया जाता है, लेकिन बढ़े हुए बिजली बिलों की इतनी शिकायत होने के बावजूद बिजली कम्पनी सुनने को तैयार नहीं है।

-महिलाएं बोली 3-4 हजार के बिल भरेंगे, तो बच्चों को क्या खिलाएंगे- स्मार्ट मीटर के खिलाफ प्रदर्शन में आमजन के साथ बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी भाग लिया और अपनी बात रखी। कुछ महिलाओं ने तो यह तक कहा कि पहले 500-600 रूपए के बिल आ रहे थे, लेकिन स्मार्ट मीटर लगने के बाद 3 से 4 हजार रूपए के बिल हर माह आ रहे हैं। ऐसे में बिजली के बिल के 3-4 हजार रूपए महिने के भर देंगे, तो बच्चों को कैसे पढाएंगे और क्या खिलाएंगे। इस दौरान एक महिला ने तो यह तक कहा कि अगर स्मार्ट मीटर से ऐसे ही बिल आएंगे, तो मीटर को उखाड़ कर फैंक देंगे। जन आंदोलन को सामाजिक संस्था कृति के किशोर जेवरिया, कांग्रेस जिलाध्यक्ष अनिल चौरसिया आम आदमी पार्टी के नवीन अग्रवाल, सीटू के शैंलेंद्रसिंह ठाकुर समेत विभिन्न लोगों ने संबोधित किया और जन आंदोलन को समर्थन दिया। इस मौके पर भगत वर्मा,कमल मित्तल,विनोद दक,मोनू लोक्स, बलवंत पाटीदार,योगेश प्रजाप्ति,रुकसान खान,भारतसिंह अहीर ,इकबाल कुरैशी,इलियास कुरैशी, राकेश सोनकर,बालचंद्र वर्मा,योगेश प्रजापति,संदीप राठौर,रणजीतसिंह बबली तंवर,हरगोविंद दीवान, ओमप्रकाश कंडारा,चेतना लालका,संजय पंवार,मीनाकुंगर, इंद्रा जयंत, सुनीता हरित,अनिता घनेटवाल, नसीम बानो, बेबी मेहरा, राजू यादव, पार्वती यादव, शाहजहा बी,मुन्नी बाई, मंगली बाई यादव,कलावती यादव समेत भारी संख्या में लोग मौजूद थे। जनता की आवाज बन श्री बाहेती ने अधिकारियों से किए सवाल जन आंदोलन के दौरान श्री बाहेती के नेतृत्व में लोगों ने सड़क पर बैठ कर प्रदर्शन किया, तो मौके पर पहुंचे एमपीईबी के अधिकारी महिप सोनी व औकांरसिंह आदि पहुंचे, जिनसे जनता की आवाज बन श्री बाहेती ने सवाल किए, जिनके जवाब जनता के समक्ष एमपीईबी अधिकारी श्री सोनी ने दिए। इस मौके पर आमजन की स्मार्ट मीटर की विभिन्न समस्याओं को लेकर एमपीईबी अधिकारियों को ज्ञापन दिया गया, जिसमें मांग की गई कि स्मार्ट मीटर की खामियों को देखते हुए नीमच शहर में स्मार्ट मीटर लगाने पर रोक लगाई जाएऔर जो मीटर लग चुके हैं, उन्हें हटाने की कार्रवाई की जाए। बिजली कंपनी स्मार्ट मीटर टेस्टिंग के नाम सिर्फ 120 मीटर लगाकर जांच कर रही है, जबकि यह संख्या 5 प्रतिशत के हिसाब से 2 हजार होना चाहिए। शासन के माध्यम से बिजली यूनिट की खपत पर सब्सिडी का दायरा बढाया जाए। मीटर खराब होने पर मीटर बदलने के नाम उपभोक्ताओं से किसी प्रकार की राशि नहीं वसूली जाए। एसएमएच चार्ज सहित अन्य तहर की वसूली पर रोक लगाई जाए। जब तक उपभाक्ताओं की शिकायत का निराकरण नहीं होता है, तब तक बिजली कनेक्शन काटने पर रोक लगाई जाए। बिजली कंपनी बिल जमा करने पर उपभोक्ताओं को मिलने वाली किस्त की सुविधा को पुन: प्रारंभ करें समेत करीब 13 बिंदु शामिल थे।

जिला मंडला,विकासखंड नैनपुर,ग्राम खम्हरिया एवम् ग्राम तिंदुआ बम्हनी में हुआ ग्राम सभा संपन्न

नैनपुर/मंडला मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 6 ,मध्य प्रदेश ग्राम सभा सम्मिलित की प्रक्रिया नियम 2001 तथा मध्यप्रदेश पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) नियम 2022 का अवलोकन ग्राम सभाओं का आयोजन! दिनांक 19/08/24 को पेसा ग्राम खम्हरिया एवम् ग्राम तिंदुआ बम्हनी में ग्राम सभा का आयोजन किया गया। जिसमें पेसा विकासखंड समन्वयक प्रतीक उइके जी की उपस्थिति में ग्राम सभा को सुचारू रूप से संचालित किया गया । सर्वप्रथम ग्राम सभा का मुख्य उद्देश्य को बताते हुए ग्राम सभा में सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुने गए अध्यक्ष- श्री डुमारू लाल मर्सकोले जी (ग्राम खम्हरिया), श्री लक्ष्मण सिंह उइके जी (ग्राम तिंदुआ बम्हनी) पंचायत राज संचनालय द्वारा दिए गए समस्त विभाग के एक-एक एजेंडा पे चर्चा कर सभी सदस्यों से उनकी राय मांगी गई। 1. पंचायती एवम् ग्रामीण विकास विभाग 2. वन विभाग 3. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग 4. सामाजिक न्याय एवं दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग 5. महिला एवं बाल विकास विभाग 6. ऊर्जा विभाग 7. प्रधानमंत्री आवास योजना एवं शासन के द्वारा जितने प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है सब पर चर्चाएं की गई। पेसा अधिनियम 2022 पर विशेष तौर से अध्यन कर मुख्य बिंदुओ पर बात रखी गई- 1. वनाधिकार अधिनियम 2006 अंतर्गत सामूहिक वनाधिकार पत्र व्यापक अभियान चलाकर प्रदत्त किये जाने के संबंध में चर्चा । 2. पेसा अधिनियम के अंतर्गत नियमानुसार 07 ग्राम समितियों का गठन । 3. पेसा अधिनियम के अंतर्गत फलिया टोलों की नवीन ग्राम सभा गठन पर चर्चा । 4. पेसा अधिनियम- तेंदुपत्ता संग्रहण के संबंध में चर्चा । 5. रुढी प्रथा, पारंपरिक ग्राम सभा स्थायी समिति का सशक्तिकरण के संबंध में चर्चा । 6. पेसा अधिनियम- बाजार मेले के संबंध में चर्चा । 7. 1) पेसा अंतर्गत समितियो का कार्यदायित्व और पुन: गठन ,2) तेंदूपत्ता संग्रहण (ग्राम खम्हरिया) , 3) नवीन ग्राम सभा का गठन (कोहका टोला) में ग्रामवासियों के द्वारा चर्चा किया गया। पेसा मोबिलाइजर के द्वारा ग्राम में प्रसाय से ग्राम को नशा मुक्त करने के लिए शपथ लिया गया। ग्रामवासियों ने एक पौधा लगाने और स्वयं उसकी देखभाल करने के लिए प्रण लिया जो की एक अच्छी पहल की शुरुवात है। ग्राम सभा में उपस्थित हुए सरपंच श्रीमती दीना कुशराम जी, सचिव श्री कोप सिंह मरकाम, पेसा विकासखंड समन्वयक श्री प्रतीक कुमार उइके, मोबिलाइजर श्री मनोज कुलेश एवं ग्राम सभा सदस्य।

चुटका निर्माण के सवालों पर व्यापक विमर्श हो

मंडला- चुटका परमाणु विरोधी संघर्ष समिति के दादु लाल कुडापे और मीरा बाई मरावी तथा बरगी बांध विस्थापित एवं प्रभावित संघ के राज कुमार सिन्हा ने संयुक्त बयान जारी करते हुए कहा है कि चुटका परमाणु संयत्र निर्माण में तेजी लाने की खबर से क्षेत्र में हलचल शुरू हो गया है।परियोजना को लेकर संगठन और विशेषज्ञों द्वारा उठाये गये सवालों का जबाब अभी तक नहीं मिला है।नर्मदा घाटी के फॉल्ट जोन और इंडियन प्लेट्स के लगातार मूवमेंट के कारण बीते तीन साल में नर्मदा और सोन नदी घाटी के जिलों में धरती के नीचे 37 बार भूकंप आ चुका है।नर्मदा घाटी में प्रस्तावित चुटका परमाणु संयंत्र के निर्माण में भी भारी तीव्रता का विस्फोट किया जाएगा।जिसके कारण भूगर्भीय हलचल होगा। आपदा प्रबंधन संस्थान, भोपाल की एक रिपोर्ट के अनुसार मंडला जिले की टिकरिया (नारायणगंज) भूकंप संवेदी क्षेत्रों की सूची में दर्शाया गया है।वर्ष 1997 में नर्मदा किनारे के इस क्षेत्र में 6.4 रेक्टर स्केल का विनाशकारी भूकंप आ चुका है।यदि दुर्घटना होता है तो आसपास के दर्जनों आदिवासी बाहुल्य गांव की आबादी को तत्काल क्षेत्र खाली कराने की क्या योजना है? परियोजना से आस्था की नदी नर्मदा के जैव विविधता, जलीय जीव और पानी की गुणवत्ता पर पडने वाले असर को कैसे संतुलित किया जाएगा?

परमाणु परियोजना को सघन सुरक्षा दायरे में रखा जाता है।इसलिए इसके बङे दायरे में किसी का भी आना- जाना प्रतिबंधित रहेगा। इस स्थिति में बरगी जलाशय से मत्स्याखेट और डूब से खुलने वाली भूमि पर खेती कर आजीविका चलाने वाले परिवारों को रोजगार देने की क्या योजना है? क्योंकि चुटका को छोडकर कुंडा और टाटीघाट की आधी आबादी तथा आसपास के दर्जनों गांव को वहीं निवास करेंगे।जिसमें नर्मदा उस पार सिवनी जिले का विस्थापित गांव भी शामिल है। बरगी बांध से उजडने के बाद विस्थापित परिवार आसपास के जंगलों और सरकारी भूमि पर खेती व बसाहट कर अपनी आजीविका चला रहा है।बहुत से ऐसे परिवार हैं जिसे उक्त भूमि का अधिकार पत्र नहीं मिलने से मुआवजा नहीं मिला है या अन्यत्र कोई जमीन के बदले जमीन देने की योजना भी नहीं है।परियोजना के लिए अधिग्रहित जमीन का मुआवजा 3.83 लाख रुपये हेक्टेयर के दर से दिया गया है जो वर्तमान दौर में नगण्य है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि परमाणु बिजली बनाने वाली इस परियोजना की वर्तमान लागत 21 हजार करोड़ रुपये है।40 साल बाद इस परियोजना की डिकमिशनिंग (परियोजना को बंद करना) करना होता है।जिसमें स्थापना खर्च के लागत के बराबर खर्च आता है।सभी खर्चे को जोङ लिया जाए तो 1मेगावाट बिजली उत्पादन की लागत 20 करोड़ रुपये आती है।जो अन्य बिजली उत्पादन के तरीके से काफ़ी महंगा है।अर्थात उत्पादित बिजली महंगी दर पर मिलेगी।ज्ञात हो कि इस संयत्र से उत्पादित बिजली का 50 प्रतिशत हिस्सा मध्यप्रदेश सरकार को खरीदना है।अभी तक मध्यप्रदेश विधुत मेनेजमेंट कम्पनी और न्यूक्लियर पावर कार्पोरेशन आफ इंडिया के बीच बिजली खरीदी अनुबंध नहीं हुआ है।प्रदेश की बिजली कम्पनी लगभग 37 हजार करोड़ के घाटे और 50 हजार करोड़ रुपये के कर्ज में डूबा हुआ है।इसलिए प्रत्येक साल विधुत कम्पनी घाटे का हवाला देकर विधुत नियामक आयोग से बिजली दर बढाते रहती है।जिससे प्रदेश की 1.50 करोड़ बिजली उपभोक्ता बिजली बिल भरने को लेकर परेशान है।अगर विधुत कम्पनी मंहगी बिजली खरीदी अनुबंध करेगी तो उसका बोझ भी आम उपभोक्ताओं को ही उठाना होगा।चुटका परमाणु विरोधी संघर्ष समिति मांग करता है कि चुटका सयंत्र से उत्पादित बिजली का दर सार्वजनिक किया जाए, स्थानीय प्रभावित होने वाले आदिवासी समुदायों की चिंताओं को केन्द्र में रखा जाए और इस परियोजना के खतरों पर नागरिक समाज के बीच व्यापक विमर्श हो।

अतिथि शिक्षकों ने नियुक्ति जल्द कराने को लेकर रैली

स्कूल खुले दो महीने हुए पूरे पर अब तक शिक्षकों का पर्याप्त इंतजाम नहीं। गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चों की पढ़ाई-लिखाई और अतिथि शिक्षकों के रोजगार की चिंता नहीं शासन-प्रशासन को

मंडला। जिले के सभी विकासखंडों से अतिथि शिक्षक बड़ी संख्या में मंडला जेलघाट में एकत्र होकर विशाल रैली के साथ सहायक आयुक्त कार्यालय व कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपनी तात्कालिक मांगों के समाधान के लिए पत्र सौंपे हैं। अतिथि शिक्षक परिवार मंडला से जिला अध्यक्ष पी.डी.खैरवार ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया है,कि मंडला जिले में स्कूलों को खुले लगभग दो माह पूरे होने वाले हैं। बावजूद इसके स्कूलों में पर्याप्त शिक्षकों का इंतजाम आज तक नहीं किया जा सका है।जो अति निंदनीय है।सर्व विदित है, कि सरकारी स्कूलों में सरकारी शिक्षकों की भारी कर्मियों के चलते 17 वर्षों से अतिथि शिक्षक नियुक्त करके ही बेहतर पढ़ाई-लिखाई की व्यवस्था बनाई जा रही है,ये अनुभवी अतिथि शिक्षक नियमित रोजगार पाने के लिए भी भारी संघर्ष कर रहे हैं। इस सत्र की पढ़ाई के लिए स्कूलों में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति अभी तक नहीं हो पाई है।जिसको लेकर तत्काल नियुक्ति के लिए आज जिम्मेदार अधिकारियों को पत्र सौंपते हुए शीघ्र ही भर्ती कराने आग्रह किया गया है। इसी तारतम्य में पत्र देने सहायक आयुक्त कार्यालय पहुंचने पर कार्यालय के जिम्मेदारों के द्वारा बताया गया,कि उनके द्वारा जिले भर के विकासखंड शिक्षा अधिकारियों और संकुल प्राचार्यों,संस्था प्रधानों को 13 अगस्त को ही पत्र लिखकर अतिथि शिक्षक भर्ती कर लिए जाने के निर्देश दिए जा चुके हैं,परंतु इस निर्देश का पालन किसी भी जिम्मेदारों के द्वारा नहीं किया जाना अनुचित है।अतिथि शिक्षकों की भर्ती में हो रही देरी के लिए जिम्मेदार संबंधित ही जिम्मेदार हैं।सहायक आयुक्त कार्यालय से आस्वस्त किया गया है,कि संबंधितों को आज ही रिमांडर लिखकर नियुक्ति जल्द दिलाने के निर्देश दिए जाएंगे ।अतिथि शिक्षकों की भर्ती जल्द हो ऐसा प्रयास किया जाएगा। अतिथि शिक्षकों ने अपने पत्र में लिखा है,कि अतिथि शिक्षकों की आनलाइन भर्ती के लिए पोर्टल अपडेशन की समस्या आ रही है तो पिछले सत्रों की ही तरह ऑफलाइन नियुक्ति दी जाए। अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति संबंधी दिशानिर्देश जनजाति कार्य विभाग के द्वारा 5/7/24 को ही जारी किये जा चुके हैं बावजूद इसके अब तक नियुक्ति नहीं दे पाना अतिथि शिक्षकों के रोजगार और गरीब व मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चों की शिक्षा के साथ घोर लापरवाही है। डीपीआई और अनुसूचित जनजाति कार्य विभाग के द्वारा दो महीने में चार से पांच बार भर्ती को लेकर आदेश पर आदेश कर तारीखें बढ़ाई जा रही हैं।जो सरकारी स्कूलों की व्यवस्था के साथ छलावा है।

कार्यालय - दिव्यांग सीडब्ल्यूएसएन छात्रावास अनूपपुर जिला अनूपपुर

क्र/**CWSN**/224/43 अनूपपुर दिनांक - 18/08/24

संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल के पत्र क्र / राशि के / आई.ई.डी/2024/2616 भोपाल दिनाँक 18/06/24 के अनुक्रम में सीडब्ल्यूएसएन दिव्यांग छात्रावास अनूपपुर में निम्नलिखित रिक्त पदों हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

क्र.	पद का नाम	पद संख्या	योग्यता
1.	अतिथि शिक्षक	01.	स्नातक एवं संबंधित स्नातक एव में बीएड / डी. एड.
2.	केयर टेकर	01.	12ठी उत्तीर्ण + कम्प्यूटर डिप्लोमा को प्राथमिकता
3.	चौकीदार	01.	12 वी उत्तीर्ण + अतिरिक्त योग्यता

टीप - आवेदनकर्ता 30/08/2024 तक संबंधित संस्था में अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

वार्डन
CWSN दिव्यांग छात्रावास
अनूपपुर
जिला - अनूपपुर (89)

पहुंचा, ऐसा करने वाली टेक के बाहर की पहली अमेरिकी कंपनी

बफेट की बर्कशायर हैथवे का बाजार मूल्य 1 ट्रिलियन डॉलर पर

इंटरनेशनल डेस्क । वॉरेन बफेट की बर्कशायर हैथवे बुधवार को 1 ट्रिलियन डॉलर के बाजार पूंजीकरण तक पहुँच गई, और इस प्रकार अमेरिका में यह प्रतिष्ठित उपलब्धि हासिल करने वाली पहली गैर-प्रौद्योगिकी कंपनी बन गई। ओमाहा, नेब्रास्का स्थित इस समूह के शेयरों में 2024 में 28त्न से अधिक की वृद्धि हुई है, जो स्×क्क500 के 18त्न लाभ से काफी अधिक है। ओरेकल ऑफ ओमाहा के 94वें जन्मदिन के ठीक दो दिन पहले कंपनी ने 1 ट्रिलियन डॉलर के मूल्यांकन की सीमा पार की। फैक्टसेट के अनुसार, बुधवार को शेयरों में 1.2त्न की वृद्धि हुई और यह 699,440.93 डॉलर के उच्च स्तर पर पहुँच गया, जिससे बाजार पूंजीकरण 1 ट्रिलियन डॉलर के निशान को पार कर गया।

ट्रिलियन डॉलर क्लब की अन्य कंपनियों (जैसे एप्पल, एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट, अमेज़ॅन, मेटा) के विपरीत, बर्कशायर का ध्यान बीएनएसएफ रेलवे, गीको इंश्योरेंस और डेयरी क्वीन जैसे पारंपरिक व्यवसायों पर है। हालांकि, इसकी बड़ी एप्पल स्थिति ने हाल ही में लाभ में योगदान दिया है। सीएफआरए रिसर्च की बर्कशायर विश्लेषक कैथी सीफर्ट ने कहा कि .1 ट्रिलियन का यह मील का पत्थर कंपनी की वित्तीय ताकत और इसके फ्रैंचाइज़ी मूल्य का प्रमाण है। उन्होंने यह भी कहा कि यह उपलब्धि महत्वपूर्ण है, खासकर जब बर्कशायर आज के समय में जीवित बचे हुए कुछ समूहों में से एक का प्रतिनिधित्व करता है।

वॉरेन बफेट ने 1960 के दशक में संघर्षरत कपड़ा व्यवसाय बर्कशायर का नियंत्रण अपने हाथ में लिया और उसे एक विशाल साम्राज्य में बदल दिया, जिसमें बीमा, रेलमार्ग, खुदरा और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में एक बेजोड़ बैलेंस शीट और नकदी किला शामिल है। हाल ही में बफेट ने रक्षात्मक मोड में रहते हुए, अपने एप्पल स्टॉक्स के आधे हिस्से को बेच

दिया और जून के अंत तक बर्कशायर के नकद भंडार को रिकॉर्ड 277 बिलियन डॉलर तक बढ़ा दिया।

हालांकि वॉरेन बफेट के बारे में जाना जाता है कि वे कभी भी बाजार का समय बताने की कोशिश नहीं करते और दूसरों को भी ऐसा करने की सलाह नहीं देते, हाल ही में उठाए गए कदमों ने वॉल स्ट्रीट पर उनके कुछ अनुयायियों को चिंतित कर दिया है। ये निवेशक मानते हैं कि बफेट ने अर्थव्यवस्था और बाजार मूल्यांकन के बारे में कुछ ऐसी चीजें देखी हैं जो उन्हें पसंद नहीं आईं। बर्कशायर हैथवे अपनी अधिकांश नकदी को अल्पकालिक ट्रेजरी बिलों में निवेश करता है, और इन प्रतिभूतियों में इसकी हिस्सेदारी - जिसकी कीमत दूसरी तिमाही के अंत में 234.6 बिलियन डॉलर थी - अमेरिकी फेडरल रिजर्व के स्वामित्व वाली राशि से अधिक हो गई है।

इसलिए यह समझना मुश्किल हो सकता है कि निवेशक बर्कशायर को 1 ट्रिलियन डॉलर के मूल्यांकन से क्यों पुरस्कृत कर रहे हैं। क्या वे अमेरिकी अर्थव्यवस्था और बफेट के विशाल व्यापारिक साम्राज्य पर दांव लगा रहे हैं, और अगर यह आगे बढ़ता रहा तो इससे लाभ होगा? या फिर वे बर्कशायर को एक नकदी किले के रूप में देख रहे हैं, जो अनिश्चित मैक्रो आर्थिक वातावरण में स्थिर आय उत्पन्न करेगा? जुलाई के मध्य में बर्कशायर ने बैंक ऑफ अमेरिका के शेयरों की बिक्री भी शुरू की, जिसमें बैंक के 5 बिलियन डॉलर से अधिक मूल्य के शेयर बेचे गए। बफेट ने 2011 में वित्तीय संकट के बाद क्क्ष्द्ध के पसंदीदा स्टॉक्स और वारंट खरीदे थे, जिससे संकटग्रस्त ऋणदाता में विश्वास बढ़ा था, जो सबप्राइम बंधक संकट से जूझ रहा था।

बर्कशायर की दूसरी तिमाही की मजबूत आय के बाद, यूबीएस विश्लेषक ब्रायन मेरेडिथ ने अपने 2024 और 2025 आय अनुमानों में वृद्धि की है। उन्होंने इसे दो कारकों का परिणाम बताया- उच्च निवेश आय और GEICO जैसे बीमा समूह में उच्च अंडरराइटिंग परिणाम। इस साल बीमा शेयरों में उछाल आया है, क्योंकि समूह महामारी के बाद कीमतों में वृद्धि जारी रखता है। मेरेडिथ को लगता है कि बर्कशायर का बाजार मूल्य .1 ट्रिलियन से कहीं अधिक बढ़ जाएगा, जिससे, शेयरों के लिए उनका 12 महीने का मूल्य लक्ष्य 759,000 हो गया है, जो बुधवार के स्तर से लगभग 9त्न अधिक है। उन्होंने इस महीने की शुरुआत में एक नोट में लिखा, हमें लगता है कि अनिश्चित मैक्रो आर्थिक माहौल में BRK के शेयर आकर्षक हैं।

रूस ने अमेरिकियों पर कसा शिकंजा

पत्रकारों सहित 92 और विशेष नागरिकों का प्रवेश किया बैन

मॉस्को। रूस के विदेश मंत्रालय ने बुधवार को ऐलान किया कि 92 और अमेरिकी नागरिकों का देश में प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है। इनमें पूर्व में रूस में काम कर चुके कुछ पत्रकार, अधिकारी और कुछ व्यापारी शामिल हैं। रूसी विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि मॉस्को को रणनीतिक रूप से हराने के घोषित लक्ष्य के साथ बाइडेन प्रशासन द्वारा अपनाई गई रूस को अलग-थलग करने की नीति के जवाब में अमेरिकियों पर प्रतिबंध लगाया गया है।

इसमें कहा गया है कि रूस और रूस सैन्य बलों के बारे में झूठी खबरें तैयार करने और उनका प्रसार करने में शामिल अग्रणी तथाकथित उदार-वैश्विक

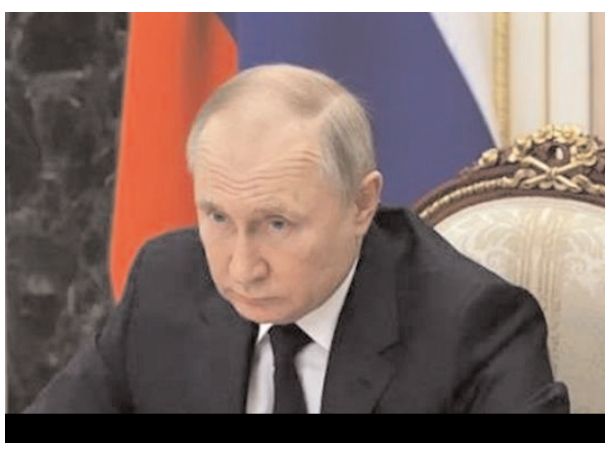

प्रकाशनों का प्रतिनिधित्व करने वाले अमेरिकी पत्रकारों पर प्रतिबंध लगाया गया है। प्रतिबंधित अमेरिकियों की नयी सूची में अंग्रेजी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की मुख्य संपादक एम्मा टकर सहित 11 वर्तमान और पूर्व पत्रकार शामिल हैं। टकर ने वॉल स्ट्रीट जर्नल के रिपोर्टर इवान गेर्शकोविच को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार करने और उनकी दोषसिद्धि के लिए रूस की बार-बार आलोचना की थी।

इवान गेर्शकोविच ने 16 महीने सलाखों के पीछे बताए थे और वह अगस्त में कैदियों की अदला-बदली के तहत रिहा हुए थे।

अमेरिकी समाचार पत्र न्यूयॉर्क टाइम्स के पांच पत्रकारों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है, जिनमें कीव ब्यूरो प्रमुख एंड्रयू क्रेमर और द वाशिंगटन पोस्ट के चार पत्रकार शामिल हैं। कानून प्रवर्तन एजेंसियों में काम करने वाले लोग, शिक्षाविद, तथा व्यवसायी और थिंक टैंक के लोगों पर भी रूस में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। मंत्रालय की सूची के अनुसार रूस ने अब तक 2,000 से अधिक अमेरिकियों के अपने यहां प्रवेश पर प्रतिबंध लगा

परेशान शख्स ने मौत को लगाया गले

लोन न चुकाने पर फाइनेंस कंपनी के कर्मियों ने घर आकर किया बेइज्जत

नेशनल डेस्क. निजी फाइनेंस कंपनी के मैनेजर और कर्मियों ने लोन की किस्त न भरने पर एक युवक को घर जाकर बेइज्जत किया। इससे आहत होकर डूडिया गांव के निवासी कर्म सिंह ने आत्महत्या कर ली। मृतक की पत्नी सिंदर कौर का आरोप है कि कंपनी के कर्मियों ने उनके पति को गालियाँ दीं और लोन न चुकाने पर घर का सारा सामान उठाने की धमकी दी। सिंदर कौर ने बताया कि वह घरेलू कामकाज करती हैं और उनकी शादी को 24 साल हो चुके हैं। उनके दो बच्चे एक 21 साल का बेटा और एक 17 साल की बेटी हैं। उनके पति ने उन्हें बताया था कि उन्होंने एसके फाइनेंस कंपनी से लोन लिया था और कंपनी के कर्मचारी बेवजह धमका रहे थे।

26 अगस्त को सिंदर कौर और उनके पति घर पर ही थे। उस दिन

दोपहर के समय फाइनेंस कंपनी के चार कर्मचारी घर आए और लोन के बारे में बात करने लगे। इनमें से हरमीत सिंह ने उनके पति को गालियाँ दीं और शाम तक लोन चुकाने का समय दिया। इसके साथ ही उन्होंने यह भी धमकी दी कि अगर लोन नहीं चुकाया तो घर का सारा सामान उठा लिया जाएगा। यह सब सुनकर उनके पति परेशान हो गए और घर से चले गए।

शाम तक जब उनके पति घर नहीं आए, तो परिवार के सदस्यों ने उनकी तलाश शुरू की। इसी दौरान पता चला कि उनके पति का शव भाखड़ा नहर के पास पड़ा हुआ है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

सिंदर कौर ने आरोप लगाया है कि उनके पति ने फाइनेंस कंपनी के मैनेजर हरमीत सिंह और अन्य तीन कर्मियों के उत्पीड़न से तंग आकर आत्महत्या की। पुलिस ने सिंदर कौर के बयान के आधार पर थाना खनौरी में फाइनेंस कंपनी के मैनेजर समेत चार कर्मियों के खिलाफ केस दर्ज किया है।

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारजेक सुलिवन ने दी जानकारी

हरदीप सिंह निज्जर की हत्या पर अमेरिका और कनाडा के बीच सहयोग की पुष्टि

इंटरनेशनल डेस्क। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने कहा है कि पिछले साल कनाडा में प्रोकलिस्तान समर्थक नेता हारदीप सिंह निज्जर की हत्या को एक हत्या के रूप में माना जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि अमेरिका और कनाडा इस मामले की जांच में पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं।

सुलिवन ने कहा, अमेरिका और कनाडा हर स्तर पर सहयोग कर रहे हैं- कानून प्रवर्तन, खुफिया, और कूटनीति में। हम किसी भी प्रकार की हत्या की कोशिशों के खिलाफ सख्त रवैया अपनाएंगे। यह एक त्रासदी है जो कनाडा में घटी है। सुलिवन ने यह बातें हैलिफ़ैक्स, नोवा स्कोटिया में एक कनाडाई कैबिनेट रिट्रीट के दौरान मीडिया के सवालों के जवाब में कही। इस दौरान उन्होंने कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और अन्य मंत्रियों से भी मुलाकात की।

18 जून 2023 को हुई थी निज्जर की हत्या

हरदीप सिंह निज्जर की हत्या 18 जून 2023 को ब्रिटिश कोलंबिया में की गई थी। तीन महीने बाद, ट्रूडो ने हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा था कि इस हत्या के भारतीय एजेंटों से संभावित संबंध होने के विश्वसनीय आरोप हैं। इस बयान से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया, क्योंकि भारत ने इन आरोपों को असंगत और प्रेरित कहा।

पिछले साल नवंबर में, न्यूयॉर्क की एक संघीय अदालत में एक आरोप पत्र जारी हुआ, जिसमें निज्जर के करीबी दोस्त और SFJ के जनरल काउंसिल गुरपतवंत पन्नू की हत्या की असफल कोशिश का उल्लेख था। अमेरिकी दस्तावेजों में एक भारतीय अधिकारी का नाम लिया गया, जिसने कथित अपराधी निक गुप्ता को पन्नू की हत्या के लिए निर्देशित किया था। यह योजना विफल हो गई क्योंकि संपर्क किए गए व्यक्ति अंडरकवर अमेरिकी ऑपरेटर थे।

निज्जर की हत्या का भी आरोप पत्र में विशेष रूप से उल्लेख किया गया। गुप्ता को चेक गणराज्य में गिरफ्तार किया गया और बाद में अमेरिका को प्रत्यर्पित किया गया, जहां वह वर्तमान में जेल में है और उसके मुकदमे का इंतजार कर रहा है। इस समय निज्जर की हत्या से जुड़े चार भारतीय नागरिक हिरासत में हैं। जांचकर्ताओं ने अभी तक भारतीय संलिप्तता के आरोपों को सिद्ध नहीं किया है, लेकिन यह पहलू अभी भी जांच में है। पिछले साल के अंत में, भारत ने पन्नू की हत्या के प्रयास की जांच के लिए एक आंतरिक समिति गठित की, लेकिन इसमें निज्जर की हत्या की जांच शामिल नहीं है।

जापान में 'शानशान से तबाही शुरु

3 लोगों की मौत, बाढ़-भूस्खलन तथा बड़े स्तर पर नुकसान की आशंका

ञ्जश्वद्म4श्च- दक्षिणी जापान में बृहस्पतिवार को भारी बारिश और तेज हवाओं के साथ आए तूफान के कारण कम से कम तीन लोगों की मौत हो गई। तूफान के और विकराल होने के चलते बाढ़, भूस्खलन तथा बड़े स्तर पर नुकसान की आशंका व्यक्त की गई है। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने बताया कि तूफान 'शानशान ने सुबह दक्षिणी क्यूशू के सतसुमासेंदाई के पास दस्तक दी, जहां 24 घंटे में 60 सेमी (23.6 इंच) तक बारिश होने के आसार हैं। इसने यह भी बताया कि तूफान के कारण देश के अधिकतर भागों, विशेषकर क्यूशू के दक्षिणी प्रान्तों में तेज हवाएं चलने, ऊंची लहरें उठने और भारी वर्षा की संभावना है और उचतम स्तर की चेतावनी जारी की गई है। जिन क्षेत्रों के लिए

चेतावनी जारी की गई, वहां के लोगों से सामुदायिक केंद्रों और अन्य जन सुविधाओं में शरण लेने की अपील की गई है।

एजेंसी ने बताया कि सुबह तक 'शानशान क्यूशू के दक्षिणी द्वीप के आसपास सक्रिय रहा, जो 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उत्तर की ओर बढ़ रहा है तथा 144 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लगातार हवा चल रही है। शहर के आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार, तूफान की दस्तक से पहले भारी बारिश के कारण भूस्खलन की घटना हुई, जिसके कारण गामागोरी में एक मकान ढह गया। इस घटना में तीन लोगों की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए। मौसम विभाग और प्रशासनिक अधिकारी बड़े स्तर पर नुकसान को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि तूफान अगले कुछ दिनों में धीरे-धीरे जापानी द्वीपसमूह को अपनी चपेट में ले लेगा। इसके कारण बाढ़ और भूस्खलन का भी खतरा है। आपदा प्रबंधन मंत्री योशिफुमी मत्सुमुरा ने कहा कि तूफान के कारण तेज हवाओं के चलने, ऊंची लहरें उठने और भारी बारिश की संभावना है। दक्षिण-पश्चिमी शहरों और द्वीपों को जोड़ने वाली सैकड़ों घरेलू उड़ानें बृहस्पतिवार को रद्द कर गईं और बुलेट ट्रेन तथा उप नगरीय रेलसेवाओं को भी रोकना पड़ा। होन्शू के मुख्य द्वीप पर भी रविवार तक इसी तरह के कदम उठाए जा सकते हैं। क्यूशू क्षेत्र में डाक और सामान पहुंचाने वाली सेवाएं भी निलंबित कर दी गई हैं और सुपरमार्केट तथा अन्य स्टोर बंद करने की भी तैयारी है।

जीवन जीने से बेहतर है मर जाना...

FB पर पोस्ट लिखने के कुछ घंटों बाद झील में मिली महिला पत्रकार की लाश

नेशनल डेस्क। बांग्लादेश के एक वरिष्ठ पत्रकार का शव उनकी एक गुप्त सोशल मीडिया पोस्ट के कुछ ही घंटों बाद एक झील में मिला है। घटना ने पूरे देश में सनसनी फैला दी है। मृतक पत्रकार ने अपनी आखिरी पोस्ट में मौत का ज़िक्र करते हुए कुछ अस्पष्ट बातें लिखी थीं, जो अब एक चेतावनी के रूप में देखी जा रही हैं।

पुलिस और जांच एजेंसियां इस मामले की तहकीकात में जुटी हैं, यह जानने के लिए कि क्या यह आत्महत्या का मामला है या किसी अपराध का। उनके परिवार और सहयोगियों ने इस मामले में गहन जांच की मांग की है, क्योंकि उनकी पोस्ट और अचानक हुई मौत के बीच का संबंध काफी संदिग्ध लग रहा है।

स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मृतका की पहचान सारा रहनुमा के रूप में हुई है, जो एक बांग्ला-भाषा के न्यूज चैनल में न्यूजरूम एडिटर थीं। रहनुमा का शव ढाका के हाटीरझील झील में बुधवार तड़के मिला। वहां से गुजरते एक

व्यक्ति ने उनके शव को झील से बाहर निकाला और ढाका मेडिकल कॉलेज अस्पताल (ष्ठस्ष्ट॥) ले गया। हालांकि, डॉक्टरों ने उन्हें स्थानीय समयानुसार लगभग 2 बजे मृत घोषित कर दिया। अस्पताल पुलिस चौकी के प्रभारी इंस्पेक्टर बचू मिया ने उनके शव की बरामदगी की पुष्टि की है। सारा रहनुमा की मौत से कुछ घंटों पहले, उन्होंने मंगलवार रात अपने फेसबुक प्रोफाइल पर दो रहस्यमय पोस्ट किए थे, जिनमें से एक पोस्ट में उन्होंने लिखा था, मृत्यु से संबंधित जीवन जीने से बेहतर है मर जाना। दूसरे पोस्ट में सारा ने फहीम फैसल नामक एक व्यक्ति को टैग करते हुए अपनी और फैसल की कुछ तस्वीरें साझा की थीं, जिनमें वे दोनों बांग्लादेश के झंडे की पट्टियां पहने हुए थे। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा, आप जैसे दोस्त का होना बहुत अच्छा था। भगवान आपका हमेशा भला करे। मुझे पता है कि हमारे पास बहुत सारी योजनाएं थीं। माफ़ कीजिए, मैं हमारी योजनाओं को पूरा नहीं कर पाऊंगी।

भगवान आपकी जिंदगी के हर पहलू में आपको आशीर्वाद दें। पुलिस ने कहा कि उनकी मौत के कारण का पता लगाने के लिए जांच की जाएगी। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बेटे सजीब वाजेद ने इसे बांग्लादेश में अभिव्यक्ति की आजादी पर एक और क्रूर हमला करार दिया है। रहनुमा के पति सैयद शुभ्रो ने बताया कि घटना वाले दिन वह रात को काम से वापस नहीं लौटीं, उन्हें सुबह 3 बजे के आसपास जानकारी दी गई कि उन्होंने हाटीरझील झील में छलांग लगा दी है। शुभ्रो ने यह भी बताया कि रहनुमा कुछ समय से उनसे अलग होना चाहती थीं।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक श्रीमती ज्योती मिश्रा द्वारा कॉम्पेक प्रिंटर्स प्रा. लि. फ्री प्रेस हाउस 3/54, प्रेस कॉम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 45ए गुप्ता चैम्बर पहली मंजिल जावरा कंपाउंड इंदौर, (म.प्र.) से प्रकाशित।
प्रधान सम्पादक : अशीष मिश्रा आर.एन.आई. पंजीयन क्रमांक : एमपी/एच/आइएन 2009/34385 फोन नं : 0731-4202569 फैक्स नं : 0731-4202569